वर्ष-8, अंक-12, दिसंबर-2023, मूल्य 5/-

कृषि भूमि

एमपी और छत्तीसगढ़: अन्नदाता के मुद्दों ने बनाई

बीजेपी की राह आसान

IFFCO

पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

50 1967 2017
स्वर्ण जयंती
Golden Jubilee

इफको के स्वर्णिम 50 वर्ष

कृषि, सहकारिता एवं ग्रामीण विकास को समर्पित

नीम लेपित यूरिया | एन पी के | डी ए पी | एन पी | बॉयो फर्टिलाइजर

वॉटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर | माईक्रो न्यूट्रीएन्ट फर्टिलाइजर

Follow us :

YouTube IFFCO live
iffcolive.com

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व

INDIAN FARMERS FERTILISER COOPERATIVE LIMITED

IFFCO Sadan, C-1 District Centre, Saket Place, New Delhi - 110017, INDIA
Phones : 91-11-26510001, 91-11-42592626. Website : www.iffco.coop

कृषि भूमि

वर्षः 8, अंकः 12, दिसंबर-2023

कविता मिश्रा

एडिटर इन चीफ

एक्जीक्यूटिव एडिटर
टी हरीश

ब्यूरो चीफ (भारत)
प्रभात तिवारी

उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ
डॉ रोहित अग्रवाल

महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ
राजेश जायसवाल

दिल्ली संवाददाता
शुभम पाण्डेय

जयपुर संवाददाता
नवीन दत्त

भोपाल संवाददाता
श्रवण प्रसाद

मुंबई संवाददाता
प्रदीप पाण्डेय

विशेष संवाददाता (दिल्ली)
अरविंद कुमार

विशेष संवाददाता (उत्तराखंड, नैनीताल)
राजू मिश्रा

विशेष संवाददाता (पूर्वोतर राज्य)
सौरभ गोस्वामी

हिंदी मासिक पत्रिका स्वामी, मुद्रक सुबोध विष्णु शंकर मिश्रा द्वारा गुड आर्ट्स प्रिंटिंग प्रेस, 118, 1st फ्लोर, श्री हनुमान इंड. स्टेट, 42-B, जी.डी. अम्बेडकर रोड, वडाला, मुंबई-400037 से मुद्रित एवं यूनीक हाईट्स बिल्डिंग, पूनम गार्डन, मीरा रोड, थाणे-401107 से प्रकाशित किया गया।

संपादक - सुबोध विष्णु शंकर मिश्रा

RNI No.: MAHHIN/2016/69098

4 अन्नदाता के मुद्दों ने बनाई बीजेपी की राह आसान

सुधारेंगी जमीन की हेल्थ... 8

मोदी सरकार बढ़ा सकती... 16

पांच साल तक गरीबों को... 24

क्या देश में शुरू होने वाला... 32

कृषि और किसानों की आवाज बनेगी 'कृषि भूमि'

कविता मिश्रा
एडिटर इन चीफ

भारत की आजादी के कई दशक बीत चुके हैं और 1947 के बाद से देश के हर क्षेत्र ने पर्याप्त विकास किया है। आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया के सफल अंतरिक्ष कार्यक्रमों में शामिल है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांच सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। अन्य क्षेत्रों में भी भारत नियमित रूप से विकास की नई गाथाएं लिख रहा है। देश के पास तमाम इन उपलब्धियों के बावजूद एक क्षेत्र ऐसा है जो अभी भी विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ है। खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार जैसे क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाने वाला कृषि क्षेत्र। जो आज तक ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचा है, जिसके बारे में हम आत्मविश्वास से कह सकें कि देश का अन्नदाता खुशहाल है। कृषि पर निर्भर देश के करोड़ों लोग आज भी घोर अभाव में जीने को मजबूर हैं और कई बार वे कृषि के माध्यम से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। वहीं कर्ज के जाल में फंसकर अपनी जीवनलीला भी समाप्त कर लेते हैं।

भारतीय कृषि के अपर्याप्त विकास की जड़ में कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिनके बिना कृषि का विकास संभव नहीं है। असल में भारत में अधिकांश किसानों के पास कृषि में निवेश के लिए पूंजी की कमी है। आज भी देश के अधिकांश किसानों को व्यावहारिक रूप से संस्थागत ऋण सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। कई बार किसानों के पास इतनी पूंजी नहीं होती कि वे बीज, खाद, सिंचाई जैसी बुनियादी चीजों का भी प्रबंध कर सकें। इसका परिणाम यह होता है कि किसान समय पर फसलों का उत्पादन नहीं कर पाते हैं या अपर्याप्त पोषक तत्वों के कारण फसलें पर्याप्त गुणवत्ता की नहीं होती हैं। इसके साथ ही पूंजी की कमी के कारण किसान को निजी व्यक्तियों से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ता है, जिससे उसकी परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ जाती है।

वहीं भारत के अधिकांश हिस्सों में अभी भी सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। सिंचाई सुविधाओं का प्रबंधन निजी तौर पर उन किसानों द्वारा किया जाता है जिनके पास पर्याप्त पूंजी उपलब्ध होती है। क्योंकि ट्यूबवेल जैसे सिंचाई उपकरण स्थापित करने की लागत ऐसी होती है कि गरीब किसानों के लिए इसे वहन करना संभव नहीं होता है। अगर बात कृषि जोत की करें तो भारतीय किसानों की एक बड़ी आबादी के पास बहुत कम कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। इसका एक बड़ा कारण बढ़ती जनसंख्या है। किसानों को अक्सर उनकी उपज का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पाता है, इसका एक बड़ा कारण यह है कि वे ऋण चुकाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम कीमतों पर अपनी फसलें बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

कृषिभूमि किसान, कृषि और उपभोक्ताओं का एक ऐसा मंच है। जो सबकी आवाज बनेगा। जब देश का किसान खुशहाल रहेगा, तभी देश में खुशहाली रहेगी और देश का हर नागरिक संपन्न होगा। क्योंकि भारत जैसे कृषि प्रधान देश की तरक्की का रास्ता खेतों के जरिए ही जाता है। आज मुझे देश के किसान, अन्नदाता और उपभोक्ताओं को कृषिभूमि का ये अंक प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है। मैं आपको आश्वस्त करती हूं कि विकास के पथ पर आपकी आवाज बनकर कृषिभूमि, कृषि से जुड़े मुद्दों को प्रमुख रूप ये सरकार और शासन के समक्ष मजबूती से सामने रखेगा।

"आजादी के बाद से देश के हर क्षेत्र ने पर्याप्त विकास किया है। आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया के सफल अंतरिक्ष कार्यक्रमों में शामिल है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांच सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। अन्य क्षेत्रों में भी भारत नियमित रूप से विकास की नई गाथाएं लिख रहा है। देश के पास तमाम इन उपलब्धियों के बावजूद एक क्षेत्र ऐसा है जो अभी भी विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ है।"

टी हरीश

एमपी और छत्तीसगढ़

अन्नदाता के मुद्दों ने बनाई

बीजेपी की राह आसान

केन्द्र की योजनाओं को जमकर भुनाया

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया कि भले ही एमपी और छत्तीसगढ़ में चुनावी मुद्दे खेतों और किसानों के इर्द-गिर्द घूमते हों, लेकिन महिला मतदाताओं ने दोनों राज्यों में भाजपा को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाई। इससे साफ है कि चुनाव में महिलाओं के जिन मुद्दों को पूरा समर्थन मिला, वे भी जो ग्रामीण और गरीब तबके से ताल्लुक रखती हैं। कुल मिलाकर एमपी और छत्तीसगढ़ में किसानों और महिलाओं के मुद्दों ने चुनाव में गांव की भूमिका को अहम बना दिया। इसका मूल कारण इन दोनों राज्यों में ग्रामीण मतदाताओं की निर्णायक भागीदारी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 15 साल बाद सत्ता में वापसी के लिए 2018 के चुनाव में किसानों के सभी तरह के कर्ज माफ करने का वादा किया था। किसानों ने इस वादे को हाथों-हाथ लिया और दोनों राज्यों में कांग्रेस सत्ता में लौट आई। लेकिन एमपी में 18 महीने की कमलनाथ सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने का फैसला किया। लेकिन इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। जिसके बाद किसानों को लगा कि उन्हें ठगा गया है और इसका गुस्सा उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पर उतारा और उसे पांच साल के लिए सत्ता से दूर कर दिया।

कांग्रेस सरकार में किसान घोषित कर दिए गए थे डिफॉल्टर: पहले चरण में मध्यप्रदेश के 40 लाख किसानों में से सहकारी समितियों का कर्ज लेने वाले 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया। लेकिन इसका असर इतना उल्टा हुआ कि 11.57 लाख किसानों को कर्ज के चंगुल से मुक्त होने के बजाय डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया था। वहीं, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने किसानों का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन किसानों को नए कर्ज से बचाने का कोई कारगर उपाय नहीं होने के कारण किसान फिर कर्ज के चंगुल में फंस गए और इसका खामियाजा कांग्रेस को चुनाव में भुगतना पड़ा था। कांग्रेस ने इस चुनाव में एक बार फिर किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया। लेकिन पिछले अनुभव से आहत किसानों ने दोनों राज्यों में कांग्रेस के इस वादे को खारिज कर दिया था और चुनाव परिणामों से यह साबित हो गया है।

एमएसपी बोनस गारंटी नहीं: किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए एमएसपी पर फसल खरीदने की गारंटी को इस चुनाव में मुद्दा बनाया गया।

किसान संगठन एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने पर अड़े थे, जबकि भाजपा और कांग्रेस किसानों से एमएसपी पर गेहूं और धान खरीदने और बोनस देने का वादा कर रहे थे। धान खरीदी पर बोनस का सफल प्रयोग करने का दावा करते हुए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने अगले कार्यकाल में 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा किया था। इसी तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर किसानों के लिए न्याय योजना के तहत गेहूं और धान खरीदने का वादा किया। लेकिन कांग्रेस किसानों को यह नहीं बता सकी कि न्याय योजना को कैसे लागू किया जाए।

किसानों को पसंद आई बीजेपी की गारंटी: भाजपा ने अपने चुनावी वादे में कांग्रेस द्वारा घोषित मूल्य से अधिक कीमत पर गेहूं और धान की खरीद को प्रमुखता दी। भाजपा ने किसानों को 2,700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं और 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा किया था। भाजपा ने किसानों का कर्ज माफ करने के बजाय ब्याज माफी योजना को बड़े पैमाने पर लागू करने का भी वादा किया। भाजपा सरकार डिफॉल्टर घोषित किए गए 12 लाख किसानों का कर्ज पहले ही माफ कर चुकी है। इस आधार पर किसानों के लिए भाजपा का ब्याज माफी का वादा कांग्रेस की कर्जमाफी से ज्यादा व्यावहारिक लग रहा था और जिसे किसानों ने चुनाव में पसंद भी किया।

बीजेपी को मुफ्त राशन गारंटी और किसान सम्मान निधि योजना से मिला फायदा: इसके अलावा गांव के गरीबों को मिल रहे मुफ्त राशन की गारंटी के अलावा एमपी में किसानों को मिल रही पीएम किसान सम्मान निधि के साथ सीएम किसान कल्याण

निधि का पैसा मिलने की गारंटी ने भविष्य में भी अपना असर दिखाया है।

गांव की गरीब महिलाओं ने पार की नावः ग्रामीण आबादी वाले मप्र में शिवराज सरकार की लाड़ली बहना और लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत निम्न आय वर्ग की महिलाओं को हर महीने एकमुश्त राशि दी जाती है। अपने चुनावी वादे में बीजेपी ने प्रमुखता से कहा कि इन दोनों योजनाओं में मिलने वाली राशि को बढ़ाया जाएगा. साथ ही यह प्रचारित किया गया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह इन योजनाओं को बंद कर देगी। लाडली योजना का पैसा शहर के गरीब परिवारों और गांव के भूमिहीन गरीब किसान परिवारों के लिए बेहतर सहारा साबित हो रहा है। वहीं किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण निधि की हकदार लघु एवं सीमान्त कृषक परिवार की महिलाओं को लाडली योजनाओं का लाभ बोनस के रूप में मिल रहा है। इस प्रकार, इन नकद देने वाली योजनाओं को अच्छी तरह से चलाने और कांग्रेस के जीतने पर उन्हें बंद करने की संभावना ने ग्रामीण मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में ध्रुवीकरण करने का पर्याप्त अवसर दिया।

40 सीटों में आधी आबादी की संख्या ज्यादाः महिलाओं को वोट देने की अधिक संभावना बनाकर, यह ध्रुवीकरण भाजपा की ऐतिहासिक जीत का आधार था। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, 40 विधानसभा सीटों पर पुरुषों की तुलना में अधिक मतदाताओं ने मतदान किया। आमतौर पर महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों की तुलना में कम होता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने भाजपा की जीत को ऐतिहासिक बनाने के लिए पुरुषों की तुलना में असामान्य रूप से अधिक मतदान किया।

पीएम किसान योजना के लिए मोदी सरकार का अभियान शुरू

45 दिन में छूटे किसानों का होगा रजिस्ट्रेशन

कृषि भूमि ब्यूरो

केंद्र सरकार ने पात्र किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने के लिए देशव्यापी संतृप्ति अभियान शुरू किया है। इस अभियान के माध्यम से योजना का लाभ पाने से छूटे हुए लोगों का पंजीयन किया जाएगा। यह अभियान 1 दिसंबर को शुरू कर दिया है और ये 45 दिनों तक चलेगा। वर्तमान में, इस योजना के तहत प्रति वर्ष 6000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ये लाभार्थियों को दिए जाते हैं जो जल्द ही 12000 रुपये होने की संभावना है।

पीएम किसान योजना किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। पीएम किसान योजना किसानों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है और वे अपनी खेती और कृषि सक्रियता में सुधार करने में सक्षम होते हैं। इस योजना के तहत देश के किसानों को हर साल 6,000 रुपये की मदद दी जाती है। पीएम किसान योजना के तहत प्रति लाभार्थी किसान के खाते में 3 बार में 2-2 हजार रुपये भेजे जाते हैं।

छूटे हुए किसानों को जोड़ने के लिए 15 जनवरी तक अभियान: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, पीएम किसान योजना का लाभ देने के लिए अभियान शुरू हो गया है। 45 दिवसीय ग्राम स्तरीय संतृप्ति अभियान 15 जनवरी 2024 तक चलेगा। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के माध्यम से देश का हर पात्र किसान इस अभियान से जुड़कर पीएम किसान योजना का लाभ उठा सकता है।

अब तक मिल चुके हैं 11 करोड़ किसानों को 2.80 लाख करोड़ रुपये: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से देशभर के 8.11 करोड़ किसानों के लिए 15वीं किस्त के रूप में कुल 18.61 हजार करोड़ रुपये जारी किए थे. वहीं, 2019 से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 2.80 लाख करोड़ रुपये की राशि 15 किस्तों में दी जा चुकी है। अब किसानों को 16वींकिस्त का इंतजार है।

किसानों को 6 हजार की जगह 12000 रुपये मिल सकते हैं: 20 नवंबर को पीएम मोदी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के तहत हनुमानगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की राशि दोगुनी करने की बात कही थी। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि राजस्थान बीजेपी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को 12,000 रुपये देने का फैसला किया है। अब राजस्थान में भाजपा की सरकार बन गई है। ऐसे में किसानों को 6000 की जगह 12000 मिलेंगे।

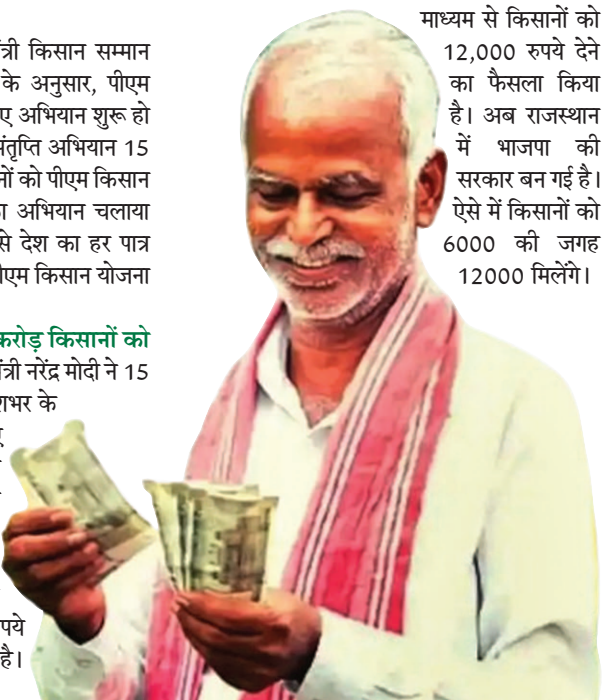

ब्रिटिश कंपनी और देश की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी इफको मिलकर

सुधारेंगी जमीन की हेल्थ

पूसा भी करेगा सहयोग

नाइट्रोजन और फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग के कारण, भारत की कृषि में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। नतीजा यह है कि ज्यादातर इलाकों का उत्पादन या तो ठप हो गया है या फिर इनकी कमी के कारण पौधों में कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। सल्फर, जिंक, बोरान, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज जैसे पोषक तत्वों की कमी ने भूमि को बीमार बना दिया है। पौधों को कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि इनकी कमी हो जाती है तो फसलों में कई तरह के रोग लग जाते हैं। सरकार भी इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही है और यहां तक कि निजी कंपनियां भी।

डॉ रोहित अग्रवाल

नाइट्रोजन और फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग के कारण, भारत की कृषि में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। नतीजा यह है कि ज्यादातर इलाकों का उत्पादन या तो ठप हो गया है या फिर इनकी कमी के कारण पौधों में कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। सल्फर, जिंक, बोरान, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज जैसे पोषक तत्वों की कमी ने भूमि को बीमार बना दिया है। पौधों को कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि इनकी कमी हो जाती है तो फसलों में कई तरह के रोग लग जाते हैं।

सरकार भी इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही है और यहां तक कि निजी कंपनियां भी। कई निजी कंपनियां विभिन्न पोषक तत्वों को बेच रही हैं। कृषि की इस कमी को पूरा करने के लिए एंग्लो अमेरिकन नामक एक अंग्रेजी कंपनी ने भारत में 'पॉली-4 ' नामक एक उत्पाद पेश किया है, जिसके बारे में एक साथ चार पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने का दावा किया जाता है। इस मौके पर इफको के एमडी डॉ यू एस अवस्थी ने नए युग के कृषि समाधानों के बारे में बात की और उर्वरकों में नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में अपने विचार साझा किए।

दावा है कि यह उत्पाद पूरी तरह से संगठित है और इसके इस्तेमाल से मिट्टी में पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम के चार तत्वों की कमी एक साथ पूरी हो जाएगी। इस कंपनी ने भारत में क्षतिग्रस्त मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान शुरू किया है। पूसा और इफको ने हाथ मिलाया है। इफको इसकी मार्केटिंग करेगी। किसानों तक पहुंचने के लिए ब्रिटिश कंपनी ने इस सप्ताह एनएएस कॉम्प्लेक्स में पूसा के सहयोग से एक सम्मेलन का आयोजन किया। जिसमें कई जाने-माने कृषि वैज्ञानिक मौजूद थे। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर मिट्टी की जांच में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है तो उसे नजरअंदाज न करें, बल्कि उसकी भरपाई करें।

गंभीर पोषण संबंधी कमियां आयी हैं भूमि में: वास्तव में, वर्तमान में, भारत के खेतों में 39 प्रतिशत जस्ता, 23 प्रतिशत बोरान और 42 प्रतिशत सल्फर की कमी है। ऐसे में पोषक तत्वों का प्रबंधन बहुत जरूरी है। इसलिए सरकार ने सल्फर लेपित यूरिया शुरू किया है। जिंक और बोरान लेपित यूरिया भी लाने की तैयारी है। ताकि इन दोनों तत्वों को जमीन पर भी सप्लाई किया जा सके। इस बीच, पोषण संबंधी कमियां, मांग को पूरा करने के लिए निजी कंपनियां भी बाजार में आ रही हैं। जिस तरह से सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपेक्षा की गई है और अब इसके दुष्प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, उससे एक नया और बड़ा बाजार दिखाई दे रहा है। बस जरूरत है किसानों को इसके प्रति जागरूक करने की।

उद्योग और उद्योग को मिलकर काम करने की जरूरत: इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. एके सिंह ने कहा कि आज कृषि क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं, उन्हें उद्योग और अनुसंधान संस्थानों द्वारा हल करने की आवश्यकता है। मृदा स्वास्थ्य, फसल उत्पादकता और मानव स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे हैं और इसे आपको हल करना होगा। इस अवसर पर चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. संजय सिंह, इफको के विपणन निदेशक डॉ. एके सिंह, योगेन्द्र कुमार, उद्यान आयुक्त डॉ. प्रभात कुमार, पूसा के प्रधान गोली वैज्ञानिक डॉ. राजीव कुमार सिंह और एंग्लो आमेर के कंट्री मैनेजर नीरज कुमार अवस्थी उपस्थित थे।

खेती के क्षेत्र में खनन कंपनी: एंग्लो अमेरिकन एक वैश्विक खनन कंपनी है जिसकी स्थापना 1917 में दक्षिण अफ्रीका में सर अर्नेस्ट द्वारा की गई थी। यह वर्तमान में दुनिया भर में 105,760 कर्मचारियों के साथ एक ब्रिटिश कंपनी है। इसका कुल राजस्व 3512.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। अब यह फसल पोषण के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है और दुनिया के कई देशों में कारोबार कर रही है।

यह दावा किया जाता है कि इसका उत्पाद मिट्टी को संरक्षित करते हुए किसानों को अधिक भोजन उगाने में मदद करता है। यह उपज, गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ा सकता है क्योंकि यह बहु-पोषक तत्व और अंग जैसा तत्व है। कंपनी ने दावा किया कि 1500 से अधिक वैश्विक वाणिज्यिक प्रदर्शनों से पता चला है कि पॉली4 के उपयोग से इसकी उपज में औसतन 3-5% का सुधार हुआ है।

उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी

पर्यटन और खेती के लिए फायदेमंद

कृषि भूमि ब्यूरो

देश में स्कीइंग के लिए मशहूर उत्तराखंड के पर्यटन स्थल औली में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी शुरू होते ही औली की वादियां सफेद बर्फ की चादर में लिपटी नजर आने लगती हैं। बर्फबारी से इस समय हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है क्योंकि पिछले तीन दिनों से मौसम लगातार रंग बदल रहा था। ऐसे में हर किसी को उम्मीद थी कि बर्फबारी होगी, ताकि आने वाले क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए औली पहुंचने वाले पर्यटक खुद का आनंद लें। आज यहां बर्फबारी से हर कोई उत्साहित है। बात चाहे पर्यटन व्यवसाय की हो या फिर स्थानीय किसानों की, क्योंकि इस बार की बर्फबारी पर्यटन व्यवसाय और खेती दोनों के लिए भी काफी फायदेमंद है। ऐसे में दिसंबर के मध्य में होने वाली यह बर्फबारी किसी के लिए फायदेमंद साबित हो रही है।

चमोली जिले के सभी ऊंचाई वाले इलाकों में इस समय भारी बर्फबारी शुरू हो गई है, पिछले तीन दिनों से मौसम लगातार रंग बदल रहा था, वहीं आज मौसम के करवट बदलने के साथ बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी के साथ-साथ ठंड में भले ही इजाफा हो रहा हो, लेकिन बर्फबारी के बाद हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है। क्योंकि बर्फबारी यहां का सबसे बड़ा पर्यटक आकर्षण है। ऐसा होता है। बर्फबारी का मतलब है कि पर्यटन कारोबार बढ़ा है, क्योंकि पिछले साल जोशीमठ आपदा के बाद औली का कारोबार पूरी तरह चौपट हो गया था। क्रिसमस और नए साल के जश्न के साथ ही औली में बर्फबारी से हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है।

हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है: चमोली जिले में दोपहर से मौसम ने करवट बदली और बर्फबारी शुरू होने के साथ ही सभी ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी देखने को मिली। वहीं बर्फबारी के बाद पहाड़ी इलाकों की खूबसूरती अपने आप में बेहद अद्भुत नजर आ रही है। तस्वीर औली जाने वाली सड़क की है जहां बर्फबारी अब औली में है यह जोशीमठ की तरफ भी होने लगी है और यहां के जंगलों की तस्वीर अपने आप में बेहद खूबसूरत लग रही है। यहां बर्फबारी के कारण हर तरफ, घर बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। वहीं, क्रिसमस और नए साल के लिए पर्यटक उत्तराखंड के औली का रुख करते हैं। यह उनके लिए तोहफा साबित होने वाला है क्योंकि इस बार समय पर बर्फबारी हुई है और अभी भी बर्फबारी जारी है।

लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है: मौसम में अचानक आए बदलाव के बाद उत्तरकाशी जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी शुरू हो गई है। यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली खुशीमठ में भारी बर्फबारी हो रही है, वहीं दूसरी ओर गंगा जी, मुखवा और हर्षिल क्षेत्रों के शीतकालीन प्रवास से भी बर्फबारी शुरू हो गई है। यमुनोत्री धाम में भी करीब 3 इंच बर्फ गिरने की खबर है, बर्फबारी के इस दौर में सीजन की यह पहली बर्फबारी है, बर्फबारी के चलते पूरा उत्तरकाशी जिला शीतलहर की चपेट में आ गया है। जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

खुशखबरीः आम लोगों को मिलेगी राहत

2024 में घट सकते हैं अनाज के दाम

कृषि भूमि ब्यूरो

अगले साल यानी 2024 में वैश्विक बाजार में अनाज की कीमतों में गिरावट आने की संभावना है। विश्व बैंक और फिच सॉल्यूशंस की शोध एजेंसी बीएमआई ने यह अनुमान लगाया है। हालांकि, उनका मानना है कि भारत द्वारा निर्यात पर लगाए गए अपवाद और अल नीनो के प्रभाव के बारे में चिंताओं को देखते हुए चावल मजबूत रह सकता है। विश्व बैंक ने अपने कमोडिटी आउटलुक में कहा है कि वैश्विक स्तर पर अनाज की आपूर्ति में सुधार के कारण मक्का और गेहूं की कीमतों में लगातार गिरावट से अगले साल चावल की ऊंची कीमतों की भरपाई होने की उम्मीद है। रिसर्च एजेंसी बीएमआई के अनुसार, सीबीओटी पर मक्का, सोयाबीन और गेहूं वायदा में 2024 में सालाना आधार पर क्रमशः 9.9 फीसदी, 3.9 फीसदी और 5.7 फीसदी की गिरावट आने का अनुमान है। 2023-24 सीजन के दौरान कई प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में बंपर पैदावार के कारण बाजार में गिरावट आ सकती है। रूस में जहां गेहूं के अधिक उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ब्राजील से वैश्विक बाजार का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे मक्का और सोयाबीन की अधिक मात्रा में आपूर्ति होने का अनुमान है।

फर्टिलाइजर की कीमतों में भी आएगी गिरावटः बीएमआई ने कहा है कि कृषि उत्पादन की लागत के संदर्भ में, ईंधन और उर्वरक की कम कीमतों से भी अगले साल अनाज की औसत कीमत में कमी आने की उम्मीद है। हालांकि, अगले एक साल में ईंधन और उर्वरक की कीमतों के लिए अभी भी जोखिम है। वहीं विश्व बैंक ने अपने कमोडिटी आउटलुक में कहा है कि खाद्य तेलों की आपूर्ति लगातार बढ़ रही है। खासकर सोयाबीन तेल की आपूर्ति में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दरअसल इस साल सोयाबीन का उत्पादन 9 फीसदी ज्यादा रहने का अनुमान है। अगले साल मक्के की कीमतों में 8 फीसदी की गिरावट आने का अनुमान है।

प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध

किसानों में नाराजगी, केन्द्र सरकार के फैसले के खिलाफ तीन प्रस्ताव पारित

शुभम पाण्डेय

केंद्र सरकार द्वारा प्याज निर्यात पर रोक लगाने के बाद महाराष्ट्र के किसानों में काफी गुस्सा है। राज्य के किसानों में केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा है। महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ ने एनएएस में एक बैठक की और सरकार के फैसले के खिलाफ तीन प्रस्ताव पारित किए। केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्याज के किसान दिल्ली आकर प्रदर्शन करेंगे। दूसरा, महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ केंद्र सरकार की प्याज आयात और निर्यात नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा। तीसरा, अब अगर महाराष्ट्र की किसी भी मार्केट कमेटी में प्याज की बोली 3000 रुपये प्रति क्विंटल से कम लगती है तो किसान प्याज की नीलामी रद्द कर देंगे। कोई भी किसान व्यापारियों को 3000 रुपये से कम कीमत पर प्याज नहीं देगा।

महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष भरत दिघोले का कहना है कि जब प्याज की कीमत सिर्फ एक और दो रुपये रह जाती है तो सरकार गायब हो जाती है। गिड़गिड़ाते रहो, कोई मदद के लिए नहीं आता। लेकिन जब कीमत थोड़ी बेहतर होने लगती है तो सरकार चिंतित होने लगती है और उसे तरह-तरह की कोशिशों से दाम मिल रहा है। जो सरकार कीमतें बढ़ने पर कीमतें कम करने में हमारी मदद नहीं कर सकती, वह ऐसा क्यों करती है? जब सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है तो हम किसानों से क्या उम्मीद करें?

सरकार पर किसानों को परेशान करने का आरोप: सरकार ने सात दिसंबर को प्याज पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद किसानों को एक दिन में करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। इसलिए महाराष्ट्र के प्याज उत्पादकों ने अब दिल्ली जाकर धरना देने का फैसला किया है। वहीं, किसान केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की कोशिश करेंगे। प्याज किसान संगठन की बैठक एनएएस में हुई इसके बाद यह फैसला लिया गया। दिघोले का कहना है कि सरकार प्याज किसानों को लगातार परेशान

कर रही है, लेकिन अब किसान अब इस तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे।

प्याज किसानों ने क्या गलत किया है ?: दिघोले का कहना है कि सरकार ने प्याज के दाम कम करने के लिए सबसे पहले अगस्त में 40 प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगाया था। उसके बाद नेफेड और एनसीसीएफ को आगे किया गया और बाजार से सस्ता प्याज बेचा गया। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। अब निर्यात पर रोक लगाने से सबसे बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार यहां के किसानों की मदद करने की कोशिश कर रही है। कोई दुश्मनी नहीं है। संगठन का सवाल है कि प्याज किसानों ने क्या किया है। क्या सरकार चाहती है कि हम प्याज की खेती बंद कर दें? अगर ऐसा होता है तो आपको 200 रुपये में प्याज खरीदना होगा। आप एक निर्यातक से आयातक बन जाएंगे।

प्याज निर्यात पर बैन के बाद किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने में जुटी सरकार, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने की समीक्षा

कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को नई दिल्ली के कृषि भवन में प्याज किसानों के मुद्दे पर एक उच्चस्तरीय बैठक की। केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर रोक लगा दी है, जिससे देशभर के प्याज किसानों में गुस्सा है। क्योंकि सरकार के इस फैसले से प्याज की कीमत काफी कम हो गई है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है। इस फैसले के बाद अब संभावना जताई जा रही है कि नेफेड किसानों से ज्यादा प्याज खरीदेगा। मुंडा ने जो बैठक ली है, उसमें प्याज की खरीद को लेकर किसानों से बातचीत हुई है। इसके जरिए किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है।

मंगलवार को नए कृषि मंत्री मुंडा ने कृषि भवन, नई दिल्ली में नेफेड, एनसीसीएफ, कृषि और खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और पूरे मुद्दे की समीक्षा की। मोदी सरकार हमेशा से देश के प्याज उत्पादक भाई-बहनों की चिंता करती रही है। यह उनके हितों के लिए भी काम करना जारी रखेगा।

कितनी होगी प्याज की खरीद: आमतौर पर नाफेड करीब तीन लाख टन प्याज खरीदता था और अपना बफर स्टॉक रखता था। लेकिन इस साल 5 लाख टन की खरीद की गई। उसके बाद जब अगस्त में प्याज निर्यात पर 40 फीसदी निर्यात शुल्क लगाया गया तो ज्यादा प्याज खरीदने का ऐलान किया गया. ताकि किसानों की नाराजगी को कम किया जा सके। कुल मिलाकर इस बार सरकार ने नेफेड को बफर स्टॉक आवंटित किया है और एनसीसीएफ को 7 लाख टन प्याज

खरीदने के निर्देश दिए गए थे। अब तक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से दो चरणों में प्याज की खरीद की जा चुकी है। वहीं, गुजरात के किसानों से प्याज खरीदने की कोशिश की जा रही है।

किसानों को सही दाम दिलाने का दावा: बैठक में अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए, एनसीसीएफ और नेफेड ने किसानों और एफपीओ के बीच जागरूकता फैलाने वाले पैम्फलेट वितरित करना शुरू कर दिया है। साथ ही, गुणवत्तापूर्ण उपज खरीदकर किसानों को सही मूल्य दिलाने के उद्देश्य से व्यापक प्रचार-प्रसार और किसानों तक पहुंचने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित किए जा रहे हैं। बैठक के दौरान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के विशेष सचिव ने कहा कि किसानों को अधिक प्याज बोने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ बैठकें की गई हैं। इस साल कम बुआई की वजह से चिंता बढ़ गई है।

प्याज की कीमतों में गिरावट की संभावना कम

प्याज की कीमतों में अभी भी गिरावट की संभावना नहीं है। क्योंकि, बारिश ने नवंबर में आने वाली फसल की आवक रोक दी है, जिससे दिसंबर में कीमतों में गिरावट की संभावनाओं को झटका लगा है। हालांकि, जनवरी 2024 में कीमतों में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। बता दें कि प्याज की कीमतों में एक साल में करीब दोगुना उछाल आया है। प्याज की कीमतों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। प्याज की वजह से नवंबर की खाद्य महंगाई दर में भी बढ़ोतरी की आशंका है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्याज की खुदरा कीमत पिछले साल के 29.76 रुपये से बढ़कर इस सप्ताह 57.85 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले अगस्त के दूसरे सप्ताह में महाराष्ट्र के थोक बाजारों में प्याज की कीमतें चढ़ने लगी थीं। अक्टूबर में नवरात्रि के बाद कुछ बाजारों में कीमतें 85 रुपये प्रति किलोग्राम को पार कर गईं।

50,000 हेक्टेयर से अधिक खड़ी फसल को नुकसान: प्याज की कीमतों में ताजा उछाल महाराष्ट्र जैसे कुछ उत्पादक राज्यों में भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई है। बारिश ने महाराष्ट्र के पुणे, नासिक, अहमदनगर और औरंगाबाद जैसे क्षेत्रों में 50,000 हेक्टेयर से अधिक में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। बारिश की वजह से बाजार में नई फसल की आवक में देरी हुई, जिसके चलते कीमतों में फिर से तेजी आ गई है।

प्याज की बुवाई-कटाई चक्र: देश में प्याज की फसल तीन चक्रों में उगाई जाती है। रबी की फसल दिसंबर-जनवरी में बोई जाती है और मार्च-अप्रैल में काटी जाती है। खरीफ फसल को जून-जुलाई में मानसून की शुरूआत के बाद बोया जाता है और सितंबर-अक्टूबर में काटा जाता है। फिर पछेती खरीफ फसल होती है जिसे सितंबर-अक्टूबर में बोया जाता है और दिसंबर-जनवरी में काटा जाता है।

आवक में देरी कीमत वृद्धि के कारण: नमी अधिक होने के कारण खरीफ की फसल का भंडारण नहीं हो पाता है और नवंबर तक बाजार में आ जाती है। हालांकि, इस साल खरीफ की फसल खराब रही, जिससे कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। खराब मौसम के कारण खरीफ प्याज की बुआई में देरी से प्याज का कवरेज कम हुआ है और प्याज की फसल की आवक में देरी हुई है। भंडारित रबी प्याज की थकावट और खरीफ प्याज की आवक से आपूर्ति में कमी की स्थिति बनी हुई है, जिससे कीमत में वृद्धि हुई है। मौसमी रूप से, प्याज की कीमतें अक्टूबर और नवंबर में बढ़ती हैं और फिर दिसंबर या जनवरी में गिरती हैं। अनुमान है कि जनवरी में प्याज की कीमतों में गिरावट आएगी।

प्याज से खाद्य मुद्रास्फीति पर पड़ेगा असर: प्याज रसोई में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है और खुदरा मुद्रास्फीति बास्केट में इसका 0.64% का भारांक है। इसलिए प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी से खाद्य महंगाई काफी बढ़ जाती है। प्याज की ऊंची कीमतों से देश भर के परिवारों को परेशानी हो रही है। अनुमान है कि नवंबर महीने के महंगाई के आंकड़े प्याज, दाल और गरम मसाला के ऊंचे दामों के कारण ऊपर जा सकते हैं।

प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र आगे

पांच राज्यों में होती है 80 फीसदी पैदावार

देश के कई राज्यों में प्याज की खेती की जाती है और साथ ही इसका इस्तेमाल शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के खाद्य पदार्थों में किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी पूरे देश में प्याज कहां से सबसे ज्यादा पहुंचता है। अगर प्याज के उत्पादन की बात करें तो महाराष्ट्र भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी प्याज उत्पादन के मामले में यह राज्य अव्वल है। यहां के किसान हर साल प्याज की बंपर पैदावार करते हैं। देश के कुल हरी मिर्च उत्पादन में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 42.73 प्रतिशत है। वहीं प्याज की खेती के लिए यहां की मिट्टी और जलवायु बेहतर मानी जाती है।

औषधीय गुणों से भरपूर है प्याजः प्याज में कई पौष्टिक और औषधीय गुण पाए जाते हैं। जिसके कारण लोग इसे खाने में पसंद करते हैं। प्याज से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है और प्याज में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर की हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। हालांकि कई लोग प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अघर बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश के किसान बड़े पैमाने पर इसकी खेती करते हैं और मध्यप्रदेश उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है। देश के कुल प्याज उत्पादन में राज्य का हिस्सा 15.23 प्रतिशत है।

सब्जी के तौर पर होता है इस्तेमालः लोग प्याज का इस्तेमाल कई तरह से करते हैं। प्याज का उपयोग सब्जी बनाने और इसके पत्तों की चटनी बनाने में किया जाता है। कर्नाटक उत्पादन के मामले में भारत के शीर्ष तीन राज्यों में तीसरे स्थान पर है। प्याज का उत्पादन 8.93 प्रतिशत है। अब जान लीजिए कि प्याज उत्पादन में गुजरात चौथे नंबर पर है। इस राज्य के किसान हर साल 8.21 प्रतिशत प्याज का उत्पादन करते हैं।

80 फीसदी प्याज का उत्पादन करते हैं पांच राज्यः राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और केंद्र सरकार (2021-22) के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान प्याज उत्पादन में पांचवें स्थान पर है। यहां के किसान हर साल 4.65 फीसदी प्याज का उत्पादन करते हैं। वहीं, ये पांचों राज्य मिलकर 80 फीसदी प्याज का उत्पादन करते हैं।

मोदी सरकार बढ़ा सकती है उर्वरकों पर सब्सिडी

कीमतों में उछाल के बाद की जा सकती है एनबीएस सब्सिडी की समीक्षा

कृषि भूमि ब्यूरो

घरेलू उर्वरक निमार्ता फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डीएपी और यूरिया की वैश्विक कीमतों में तेज वृद्धि से चिंतित हैं। क्योंकि, इससे घरेलू विनिमार्ताओं को मिल रही पोषक तत्व आधारित सब्सिडी प्रभावित हो रही है। ऐसे में विनिमार्ताओं ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) बढ़ाने के लिए समीक्षा की मांग की है। उर्वरक निमार्ता बढ़ती वैश्विक कीमतों के कारण एनबीएस सब्सिडी की समीक्षा चाहते हैं। संभव है कि सरकार जल्द ही कोई फैसला ले सकती है। डीएपी यानी डी-अमोनियम फॉस्फेट की वैश्विक कीमतें जुलाई के 440 डॉलर प्रति टन से बढ़कर अब 590 डॉलर प्रति टन हो गई हैं। उर्वरक कंपनियों का कहना है कि मौजूदा खुदरा मूल्य को बनाए रखने के लिए फास्फोरस में सब्सिडी का स्तर बढ़ाने की जरूरत है। फास्फोरस का उपयोग उर्वरक में किया जाता है। फास्फोरस पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने और पौधों के बेहतर विकास में मदद करता है। रबी 2023 सीजन के लिए, डीएपी 1,350 रुपये प्रति 50 किलोग्राम बैग पर बेचा जा रहा है। सरकार ने फास्फोरस पर सब्सिडी को पिछले रबी सत्र में 66.93 रुपये प्रति किलोग्राम से घटाकर 20.82 रुपये प्रति किलोग्राम और खरीफ 2023 में 41.03 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया था।

अप्रैल-अक्टूबर में यूरिया की बिक्री 8 प्रतिशत बढ़ीः चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अक्टूबर के दौरान यूरिया की बिक्री आठ प्रतिशत बढ़कर 207.63 लाख टन रही जो एक साल पहले इसी अवधि में 192.61 लाख टन थी। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएआई) के अध्यक्ष एन सुरेश कृष्णन ने कहा कि वैश्विक स्तर पर गैर-यूरिया उर्वरकों में डीएपी की कीमत सबसे अधिक है। जबकि भारत में यह एमओपी और कॉम्प्लेक्स से कम है, यह सुझाव देते हुए कि इसे नीतिगत परिवर्तनों के साथ संबोधित किया जाना चाहिए।

एनबीएस सब्सिडी पर प्रतिकूल प्रभावः विशेषज्ञों और विनिमार्ताओं ने कहा कि उर्वरक के असंतुलित उपयोग से मुख्य रूप से 45 किलोग्राम के बैग पर 267 रुपये की अत्यधिक रियायती दर है। सरकार भारत के पड़ोसी देशों समेत अन्य देशों में यूरिया की ऊंची दरों की तुलना करते हुए इसे अपनी उपलब्धि बता रही है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव और रबी 2023-24 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों में गिरावट फास्फोरस और पोटाश डूइंग को प्रभावित करेगी।

नैनो यूरिया के लॉन्च के बाद आयात शून्य हो जाएगाः विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में पोटास के लिए एनबीएस दरों में तेज कमी मिट्टी में महत्वपूर्ण प्राथमिक पोषण तत्व की

उपलब्धता को प्रभावित कर रही है और एनपीके उपयोग अनुपात को और बढ़ा रही है। यह बताते हुए कि भारत उर्वरकों के लिए विभिन्न कच्चे माल और फीडस्टॉक के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। एन सुरेश कृष्णन ने कहा कि बिना सब्सिडी वाले नैनो यूरिया की क्षमता वृद्धि और लॉन्च के साथ, कुछ वर्षों के बाद यूरिया का शून्य आयात हो सकता है।

बेमौसम बारिश से महंगी हुई खाने की थाली, सब्जियों और दालों को हुआ नुकसान

कृषि भूमि ब्यूरो

महाराष्ट्र की बेमौसम बारिश से सब्जियों, अंगूर, प्याज, कपास, चना और अरहर की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अब बाजार में प्याज और सब्जियों की आवक कम होने की आशंका है। महाराष्ट्र के 22 जिलों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। इससे नुकसान का रकबा तीन गुना बढ़ गया है और सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। अब बाजार में प्याज और सब्जियों की कमी होने की आशंका है। यानी आने वाले दिनों में इनकी कीमतों में और इजाफा हो सकता है।

विदर्भ का यवतमाल जिला हाल की बारिश और ओलावृष्टि से सबसे ज्यादा प्रभावित है। बेमौसम बारिश की वजह से 1,26,438 हेक्टेयर में लगी खेती को नुकसान पहुंचा है। सब्जियां, अंगूर, प्याज, कपास,चना और अरहर की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। इसके अलावा कई जिलों में केले की खेती और धान, गेहूं और मिर्च की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। अगर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों की बात करें तो पिछले एक साल में प्याज और टमाटर के दाम लगभग दोगुने हो गए हैं. दिल्ली में प्याज की औसत कीमत एक साल पहले 30 रुपये थी, जो बढ़कर 60 रुपये प्रति किलो हो गई है। मुंबई में यह 31 से 56 पर पहुंच गया है, जबकि कोलकाता में यह 63 रुपये पर पहुंच गया है।

टमाटर की कीमतों में आयी तेजी: एक साल पहले दिल्ली में टमाटर 30 रुपये में बिका था। अब यह 60 रुपये तक पहुंच गया है। कोलकाता में यह अब 60 रुपये है। मुंबई में यह 18 रुपये से बढ़कर 50 रुपये हो गया है। आलू की बात करें तो इस दौरान दिल्ली में राहत मिली है। यह एक साल पहले के 28 रुपये की तुलना में 24 रुपये पर है। मुंबई में यह 33 की जगह 31 रुपये और कोलकाता में महज 21 रुपये है।

दाल ने बिगाड़ा रसोई का बजट: एक साल पहले दिल्ली में 72 रुपये किलो बिकने वाली चना दाल अब औसतन 88 रुपये के भाव पर बिक रही है। मुंबई में यह 89 रुपये से 123 रुपये तक पहुंच गया है। अरहर दाल भी दिल्ली में 115 से 170 रुपये तक पहुंच गई है। मुंबई में यह 121 से 182 रुपये पर पहुंच गया है।

दाल की कीमतों में आया उछाल: उड़द दाल भी दिल्ली में 117 से 143 रुपये प्रति किलो और मुंबई में 130 से 171 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। दिल्ली में पिछले साल मूंग दाल 15 रुपये प्रति किलो महंगी हो चुकी है। मुंबई में यह 118 रुपये से 163 रुपये तक पहुंच गया है। मसूर दाल दिल्ली में 92 रुपये से घटकर 90 रुपये पर आ गई है, जबकि मुंबई में यह 102 रुपये से घटकर 115 रुपये पर पहुंच गई है।

बाजार में लगातार बढ़ रही मांग, पिछले एक साल में

मोटे अनाज के दाम दोगुने

कृषि भूमि ब्यूरो

पिछले एक साल में मोटे अनाज की कीमत दोगुनी हो गई है। रागी, ज्वार, ब्राउन टॉप सहित अन्य मोटे अनाजों की कीमतें पिछले एक साल में 40-100 प्रतिशत तक बढ़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष अभियान और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इस क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ, बाजरा की मांग बढ़ रही है। इसके अलावा अनियमित मौसम की वजह से भी इसकी आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से कीमतों में उछाल दर्ज किया गया है।

उद्योग का कहना है कि बाजरा से बने बाजरा से बने पास्ता, नूडल्स और स्नैक्स जैसे नए उत्पादों के लॉन्च होने, नाश्ते में मोटे अनाज को शामिल करने और पारंपरिक आटे के स्थान पर बाजरा की बढ़ती खपत ने बाजरा की मांग को बढ़ावा दिया है । इसके अलावा, बाजरा आधारित स्टार्टअप, जो वार्षिक आधार पर दोगुनी दर से बढ़ रहे हैं। वहीं मोटे अनाज उगाने वाले क्षेत्रों में अनियमित रूप से बढ़ने की अनुमति दी गई है। गेहूं और चावल की तुलना में कम उत्पादन के साथ मौसम की स्थिति ने अच्छी गुणवत्ता वाले बाजरा की पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया है।

सूखे और बारिश के कारण कम हुआ उत्पादनः मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना के ज्वार उत्पादक क्षेत्रों में सूखे और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के फसल उत्पादक क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश के कारण बाजरा उत्पादन में गिरावट आई है, जिससे कीमतों में वृद्धि हुई है। उद्योग के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि गेहूं की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाले ज्वार और रागी की कीमतें क्रमशः 150 प्रतिशत और 45 प्रतिशत हैं। यह और अधिक महंगा हो गया है। उनका कहना है कि हर महीने मोटे अनाज की कीमतों में 15-20 फीसदी की बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही इनकी कीमतों में भी काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।

मिलेट्स स्टोर खोलने के लिए अब किसानों को 20 लाख का अनुदान देगी योगी सरकार, 11 दिसंबर से आवेदन शुरू

साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसके तहत योगी सरकार श्रीयन और उससे जुड़े किसानों के उत्थान पर भी विशेष कार्य कर रही है। हाल ही में योगी सरकार ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्रीअन्न महोत्सव और कार्यशाला का भी आयोजन किया था। वहीं, उत्तर प्रदेश बाजरा पुनरोद्धार कार्यक्रम के तहत योगी सरकार बाजरा बीज उत्पादन के लिए बीज धन, बाजरा प्रसंस्करण, पैकिंग विपणन केंद्र, बाजरा मोबाइल आउटलेट और बाजरा

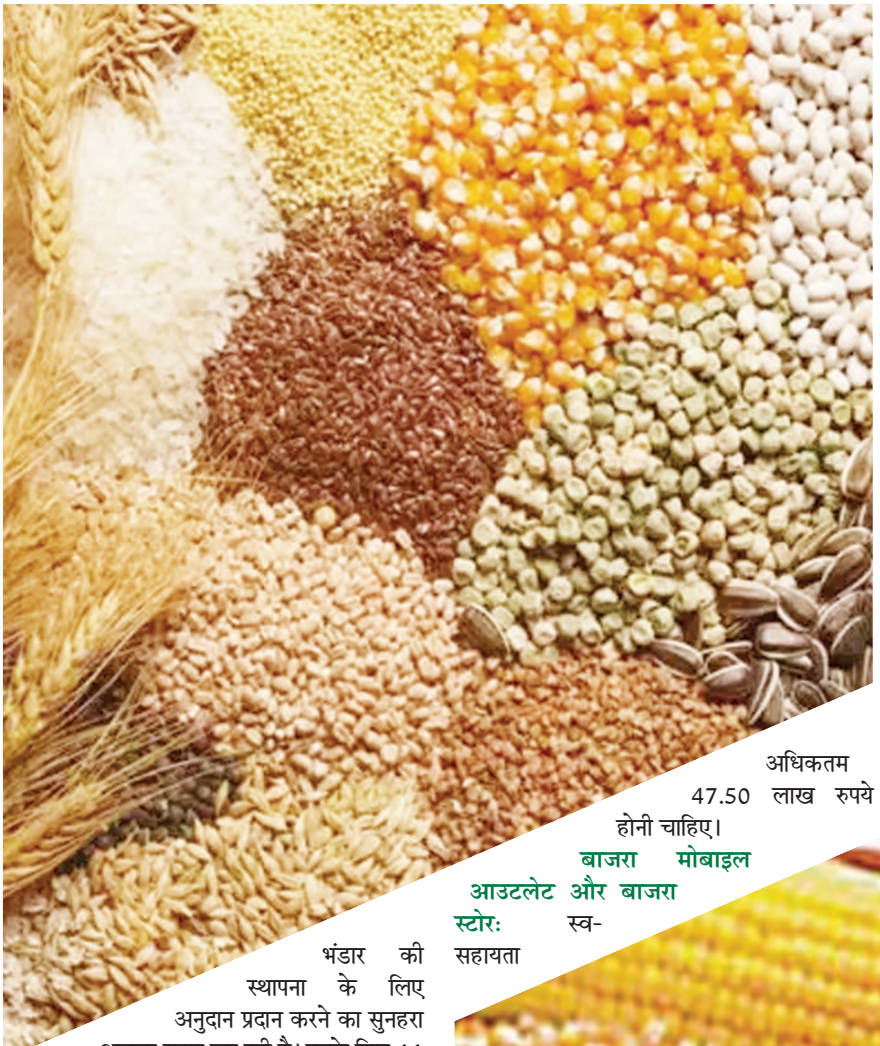

भंडार की स्थापना के लिए अनुदान प्रदान करने का सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है। इसके लिए 11 दिसंबर दोपहर 12 बजे से 16 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन/बुकिंग की गई। स्वयं सहायता समूह/किसान उत्पादक संगठन/उद्यमी/किसान बाजरा की किसी भी एक मोबाइल दुकान/बाजरा स्टोर के लिए आवेदन करेंगे।

बाजरा बीज उत्पादन के लिए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) सीडमनी के तहत आवेदन कर सकेंगे। इस पर प्रति एफपीओ 4 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत केवल वही एफपीओ लाभ ले सकेंगे जिन्होंने खरीफ-2023 में बाजरा बीज का उत्पादन किया हो और 100 क्विंटल बाजरा के विभिन्न फसलों के बीज निकालकर सही प्रक्रिया से स्टोर किए गए हों।

बाजरा प्रसंस्करण और पैकिंग विपणन केंद्रः वहीं, बाजरा प्रसंस्करण और पैकिंग विपणन केंद्र के लिए उद्यमी और किसान उत्पादन संगठन (एफपीओ) भी आवेदन कर सकते हैं. एफपीओ कम से कम तीन साल पुराने हैं और उनका कारोबार 100 लाख रुपये है, तभी उन्हें पात्र माना जाएगा। अनुदान के लिए पात्रता डीपीआर के अनुसार लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 47.50 लाख रुपये होनी चाहिए।

बाजरा मोबाइल आउटलेट और बाजरा स्टोरः स्व-सहायता समूह/किसान उत्पादक संगठन/उद्यमी/किसान बाजरा मोबाइल आउटलेट और बाजरा स्टोर के लिए आवेदन कर सकते हैं। डीपीआर के अनुसार, बाजरा मोबाइल आउटलेट के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये और बाजरा स्टोर के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता के अनुसार उसकी आयु कम से कम तीन वर्ष होनी चाहिए तथा मोबाइल आउटलेट एवं बाजरा दुकान के लिए वाहन उपलब्ध होना चाहिए। आवेदक संस्था का बैंक खाते में 10 लाख रुपये की पूंजी होना भी अनिवार्य है।

क्या है आवेदन की प्रक्रियाः आवेदन के लिए पात्रता सर्वेक्षण और आवेदन की पूरी प्रक्रिया विभागीय पोर्टल (www.agriculture.up.gov.in) पर उपलब्ध है)। आवेदक को विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उपलब्ध लिंक पर विवरण भरकर विवरण प्रस्तुत करना होगा। पंजीकरण का प्रिंट प्राप्त होने पर, आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले रिकॉर्ड की एक चेकलिस्ट भी प्राप्त होगी। पंजीकरण का प्रिंट आवेदक द्वारा अन्य सभी वांछित अभिलेखों के साथ संबंधित जिला उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा किया जाएगा।

उर्वरता

खो रही है बिहार की मिट्टी

कृषि वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

कृषि भूमि ब्यूरो

बिहार के किसानों के लिए चिंता की खबर है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रदेश की मिट्टी की उर्वरा शक्ति तेजी से घट रही है। फसलों के लिए जरूरी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक जैसे पोषक तत्वों की भारी कमी है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध और अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो हमारे खेतों की भी वही हालत होगी जो पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की है। खेती की भूमि बंजर या कम उपज वाली हो जाएगी। बिहार सरकार ने कृषि के समग्र विकास के लिए कृषि रोडमैप बनाकर एक बड़ी पहल की। तीसरा रोडमैप जारी है, चौथा लाने की कवायद चल रही है। इसके सार्थक परिणाम भी सामने आए हैं। राज्य में हर साल खाद्यान्न सहित फलों और सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। लेकिन मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने की एक नई चुनौती है।

नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा में आ रही है कमी: राज्य की मिट्टी में मूल्यवान पोषक तत्वों में प्रमुख नाइट्रोजन की मात्रा में 60 प्रतिशत, फास्फोरस में 45 प्रतिशत, पोटाश में 28 प्रतिशत, जस्ता में 42 प्रतिशत , बोरान में 18 प्रतिशत की और सल्फर 24 प्रतिशत तक कमी आयी है। वैसे यह स्थिति लगभग पूरे देश में है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी मृदा स्वास्थ्य से जुड़ी रिपोर्ट में भी यह बात सामने आई है। बिहार की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी अधिक पाई गई है। लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्रों में मिट्टी में इसकी कमी है। मिट्टी की आत्मा माने जाने वाले ऑर्गेनिक कार्बन में 40 फीसदी की कमी आई है। इसका सीधा असर सभी तरह की फसलों की गुणवत्ता पर भी पड़ रहा है।

इन जिलों में कृषि पर अधिक प्रभाव: पूरे बिहार की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आम बात है।

लेकिन मुजफ्फरपुर और पश्चिम चंपारण सहित कुछ अन्य स्थानों पर, मिट्टी अत्यधिक क्षारीय या अम्लीय हो गई है। किसी भी चीज की खेती करना संभव नहीं है। हालांकि विभाग स्तर पर इसका तेजी से इलाज किया जा रहा है। संभावना है कि यह कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा। अगर हम अभी से मिट्टी की सेहत को लेकर सचेत नहीं हुए, तो कई जिलों में ऐसी ही स्थिति होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार, 15 प्रतिशत मृदा स्वास्थ्य खराब हो गया है।

पोषक तत्वों में कमी के कारण आ रही है परेशानी: सबौर कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान विशेषज्ञ डॉ. सुनील कुमार का कहना है कि मिट्टी में 17 से अधिक पोषक तत्व होते हैं, जो पौधों की उचित वृद्धि के लिए जरूरी हैं। इसे मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश सहित छह बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की उचित मात्रा बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इनकी कमी के कारण बिहार में मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है।

देश में हो सकता है गेहूं संकट

सरकारी स्टॉक 7 साल के निचले स्तर पर

कृषि भूमि ब्यूरो

गेहूं की महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा खुले बाजार में गेहूं की बिक्री बढ़ाने का असर सरकार के गेहूं स्टॉक पर पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 1 दिसंबर तक 190 लाख टन तक पहुंच गया, जो दिसंबर की शुरूआत में 7 साल में सबसे कम स्टॉक है। ऐसे समय में गेहूं के स्टॉक में गिरावट आई है, जब देश में गेहूं की खेती पिछले साल की तुलना में पिछड़ रही है, देश में गेहूं का कुल रकबा 8 दिसंबर तक लगभग 249 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 251 लाख हेक्टेयर से अधिक था। हालांकि सरकार का दावा है कि गेहूं आयात करने की नौबत नहीं आएगी। क्योंकि कई राज्यों में मार्च से नया गेहूं बाजार में आ जाता है। स्टॉक में गिरावट के कारण देश में गेहूं आयात की संभावना प्रबल हो गई है। आटा मिलें अपना परिचालन जारी रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जा रही नीलामी से गेहूं खरीद रही हैं। गेहूं की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए खुले बाजार में अधिक मात्रा में गेहूं बेचने के सरकार के कदम के बाद भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास मौजूद स्टॉक अगले वित्त वर्ष की शुरूआत तक बफर आवश्यकता से नीचे आने की संभावना है।

एफसीआई का बफर स्टॉक आ सकता है नीचे: चालू वित्त वर्ष में खुली बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत बिक्री के लिए मंजूर एक करोड़ टन के अलावा 25 लाख टन के अतिरिक्त आवंटन से एफसीआई के पास गेहूं का भंडार एक अप्रैल तक 74.8 लाख टन के बफर स्तर से नीचे आ सकता है। एफसीआई ने चालू वित्त वर्ष में जून से अब तक साप्ताहिक ई-नीलामी के माध्यम से अपने स्टॉक से 44.6 लाख टन गेहूं बेचा है और ई-नीलामी के लिए गेहूं का साप्ताहिक आवंटन 20 दिसंबर से बढ़ाकर चार लाख टन कर दिया गया है।

खुशखबरीः सरकार ने खुले बाजार में जारी किया 2.84 लाख टन गेहूं, 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगा भारत ब्रांड आटा

देश की आम जनता को केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकारी ने राहत दी है। जिसके बाद रोटी अब सस्ती हो सकती है। असल में केंद्र सरकार ने बढ़ते आटे की कीमत को नियंत्रित करने के लिए कमर कस ली है और सरकार ने बुधवार को ई-नीलामी के जरिए खुले बाजार में 2.84 लाख टन गेहूं बाजार में उतारा है। सरकार को उम्मीद है कि उसके इस फैसले से खुदरा बाजार में गेहूं की आवक बढ़ेगी, जिससे आटे के दाम में गिरावट आ सकती है। खास बात यह है कि केंद्र ने 28 जून से अब तक 42 फीसदी सरकारी स्टॉक इकट्ठा किया है। सरकार पहले ही ई-नीलामी के माध्यम से 100,000 टन गेहूं बेच चुकी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की मदद से गेहूं बेच रही है। इस बार ई-नीलामी के दौरान बोलीदाताओं ने 2128 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं की बोली लगाई, जो लगभग पिछले एक सप्ताह के रेट के बराबर है। लेकिन, गेहूं का औसत बिक्री मूल्य 2279 रुपये प्रति क्विंटल था। एक अधिकारी ने बताया कि पिछली गेहूं नीलामी में 2420 बोलीदाताओं ने हिस्सा लिया था और व्यापारियों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। दरअसल, एफसीआई चाहता है कि ई-नीलामी के जरिए सिर्फ प्रोसेसर को ही गेहूं मिले, ताकि आटा, मैदा और सूजी की कीमतें नियंत्रण में रहें।

गेहूं की औसत कीमतों में वृद्धिः गेहूं की ई-नीलामी भी 15 नवंबर को हुई थी। इस दौरान गेहूं का औसत बिक्री मूल्य 2,251.79 रुपये प्रति क्विंटल से घटकर 2,233.61 रुपये प्रति क्विंटल रह गया। तथापि, पिछले दो दौर की नीलामी के दौरान गेहूं के औसत मूल्य में वृद्धि हुई है। वहीं, सरकार ने अगले रबी विपणन सत्र 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,125 रुपये से बढ़ाकर 2,275 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है।

व्यापारियों को नीलामी से किया है बाहरः एक आटा मिल मालिक ने कहा कि 31 मार्च तक एफसीआई 48-50 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेच सकता है। जिसके कारण आटे की कीमत पर कंट्रोल हो सकता है। इससे अगले साल 31 मार्च तक करीब 90 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचा जा सकेगा। हालांकि, सरकार ने गेहूं की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। जबकि केवल प्रोसेसर को भाग लेने की अनुमति देकर व्यापारियों को नीलामी से बाहर कर दिया गया है।

2.28 लाख टन गेहूं का आवंटन किया गयाः सरकार ने सफल बोलीदाताओं को रिलीज ऑर्डर जारी करने से पहले पिछले तीन महीनों के प्रसंस्करण संयंत्र/इकाई के बिजली बिलों का सत्यापन भी शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने कहा कि यह मुख्य रूप से व्यापारियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नीलामी से बाहर रखने के लिए किया जाता है।

27.50 रुपये प्रति किलोग्राम में मिलेगा भारत ब्रांड आटाः इसके अलावा, अनाज को आटे में बदलने और 'भारत आटा' ब्रांड के तहत जनता को बेचने के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जाएगा। इसके लिए सहकारी संगठनों, केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ और नेफेड को रियायती दरों पर 2.28 लाख टन गेहूं आवंटित किया गया है।

मोदी सरकार का बड़ा फैसला

पांच साल तक गरीबों को मिलेगा

मुफ्त अनाज

कृषि भूमि ब्यूरो

केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने गरीबों को मिलने वाले राशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 81 करोड़ गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया है। असल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (29 नवंबर) को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कैबिनेट ने फैसला किया है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत करीब 81.35 करोड़ लाभार्थियों को एक जनवरी 2024 से पांच साल की अवधि के लिए मुफ्त अनाज मुहैया कराएगी। केन्द्र सरकार ने ये फैसला राज्यों में चुनावों के संपन्न होने के बाद लिया है।

यह निर्णय पीएमजीकेएवाई योजना को दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए है। इसका उद्देश्य 5 वर्षों के लिए 81.35 करोड़ व्यक्तियों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना पर 11.80 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी। यह योजना एक समान लोगो के तहत 5 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मुफ्त खाद्यान्न वितरण में राष्ट्रव्यापी एकरूपता प्रदान करेगी।

वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत भी मिलेगा राशनः यह ओएनओआरसी-वन नेशन वन राशन कार्ड पहल के तहत लाभार्थियों को देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से मुफ्त में खाद्यान्न उठाने की अनुमति देकर जीवन को आसान बनाने में सक्षम करेगा। यह पहल प्रवासियों के लिए बहुत फायदेमंद है, जो डिजिटल इंडिया के तहत प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों के हिस्से के रूप में अधिकारों की अंतर और अंतर-राज्य पोर्टेबिलिटी दोनों की सुविधा प्रदान करती है। मुफ्त खाद्यान्न एक साथ देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के तहत पोर्टेबिलिटी के समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा और इस पसंद-आधारित मंच को और मजबूत करेगा।

बंपर कमाई का जरिया है हरी मिर्च, उत्पादन में आंध्र प्रदेश अव्वल

खाने की प्लेट में अगर हरी मिर्च ना हो तो व्यंजनों का स्वाद अधूरा है। हरी मिर्च अपने तीखेपन के लिए जानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हरी मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी पूरे देश में हरी मिर्च सबसे ज्यादा कहां से पहुंचती है? आंध्र प्रदेश भारत में हरी मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी हरी मिर्च उत्पादन के मामले में यह राज्य अव्वल है और यहां के किसान हर साल मिर्च की बंपर पैदावार करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश के कुल हरी मिर्च उत्पादन में आंध्र प्रदेश की हिस्सेदारी 18.75 प्रतिशत है। हरी मिर्च की खेती के लिए यहां की मिट्टी और जलवायु बेहतर मानी जाती है। हरी मिर्च का इस्तेमाल खाने का जायका बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसलिए कर्नाटक के किसान बड़े पैमाने पर इसकी खेती करते हैं और अगर उत्पादन की बात की जाए तो इस मामले में कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। देश के कुल हरी मिर्च उत्पादन में राज्य का हिस्सा 18.62 प्रतिशत है।

औषधीय गुण भी हैं मिर्च में: हरी मिर्च की खासियत सिर्फ तीखेपन के लिए ही नहीं है बल्कि कई वैज्ञानिक शोधों में भी इसके औषधीय गुणों की पुष्टि हो चुकी है। मध्य प्रदेश उत्पादन के मामले में भारत के शीर्ष तीन राज्यों में तीसरे स्थान पर है। यह 12.56 प्रतिशत हरी मिर्च का उत्पादन करता है। मिर्च एक नकदी फसल है। इसकी खेती से अधिक लाभ कमाया जा सकता है. अब जान लीजिए कि हरी मिर्च के उत्पादन में बिहार चौथे स्थान पर है। इस राज्य के किसान हर साल 12.10 प्रतिशत हरी मिर्च का उत्पादन करते हैं।

विटामिन सी और फास्फोरस है मौजूद: अगर सेहत के नजरिए से देखा जाए तो मिर्च का सेवन हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है. क्योंकि इसमें विटामिन ए और फास्फोरस होता है। महाराष्ट्र ने हरी मिर्च उत्पादन में अपना पांचवां स्थान बरकरार रखा है। यहां के किसान हर साल 9.53 प्रतिशत हरी मिर्च का उत्पादन करते हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (2021-22) के आंकड़ों के अनुसार, झारखंड हरी मिर्च की पैदावार में छठे स्थान पर है. यहां के किसान हर साल 7.05 प्रतिशत हरी मिर्च का उत्पादन करते हैं। वहीं, ये छह राज्य मिलकर 70 फीसदी हरी मिर्च का उत्पादन करते हैं।

तेलंगाना में सरकार ने किसानों को दिया तोहफा

'रायथू बंधु' योजना से मिलेगा पैसा

कृषि भूमि ब्यूरो

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सोमवार को अधिकारियों को राज्य में नई सरकार के गठन के बाद 'रायथू बंधु' योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता देने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक बैठक में, रेड्डी ने कृषि विभाग और उसके सहयोगी विंग के कामकाज और प्रदर्शन और किसानों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर व्यापक चर्चा की। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सोमवार से ही किसानों के खातों में 'रायथू बंधु' योजना के तहत वित्तीय सहायता जमा करना शुरू कर दें। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि किसी भी किसान को असुविधा न पहुंचाए जल्द से जल्द सहायता प्रदान की जाए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों से चुनाव से पहले किए गए वादे के मुताबिक 2 लाख रुपये देने को भी कहा। पार्टी ने सरकार से सत्तारूढ़ कांग्रेस के 10,000 करोड़ रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने के चुनाव पूर्व वादे को लागू करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने को भी कहा।

प्रजा दरबार को कहा जाएगा प्रजा वाणी: रेड्डी ने कहा कि ज्योतिराव फुले प्रजा भवन (मुख्यमंत्री का शिविर कार्यालय-आधिकारिक आवास) में आयोजित होने वाले 'प्रजा दरबार' को अब 'प्रजा वाणी' कहा जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि 'प्रजा वाणी' मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग सुबह 10 बजे हैं। जो लोग सीएम से पहले प्रजा भवन पहुंचते हैं, उन्हें अपने आवेदन जमा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। रेड्डी ने अधिकारियों से दिव्यांग लोगों और महिलाओं के लिए अलग-अलग कतारें लगाने और 'प्रजावाणी' में आने वाले लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा।

किसानों को 10 हजार की आर्थिक मदद दी जाती है: तेलंगाना में किसानों को रायथू बंधु योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, राज्य के किसानों को रबी और खरीफ दोनों मौसमों के लिए 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्य में चुनाव के कारण आचार संहिता लागू होने के कारण किसानों को इस बार पैसा मिलने में देरी हुई। हालांकि, चुनाव आयोग ने पहले किसानों को 28 नवंबर तक पैसे का भुगतान करने का निर्देश दिया था, लेकिन बाद में कांग्रेस की आपत्ति के बाद योजना के तहत पैसे ट्रांसफर करने के फैसले पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद फिर से पैसे देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

भूटान को 9 लाख टन आटा और सूजी निर्यात करेगा भारत

पांच देशों को चावल भी बेचेगा

कृषि भूमि ब्यूरो

केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने टूटे हुए चावल और गेहूं के निर्यात की अनुमति दे दी है। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से 5 देशों को लगभग 9 लाख टन टूटे हुए चावल का निर्यात किया जाएगा। इसके अलावा भारत ने अपने पड़ोसी देश भूटान को 34,000 टन से अधिक गेहूं और गेहूं उत्पादों के निर्यात की घोषणा की है। कहा जा रहा है कि वाणिज्य मंत्रालय ने अन्य देशों के अनुरोध के आधार पर चावल और गेहूं के निर्यात की अनुमति दी है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, उसने मानवीय और खाद्य सुरक्षा के आधार पर टूटे हुए चावल, गेहूं और गेहूं उत्पादों के निर्यात के लिए कोटा आवंटन निर्धारित दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं को भी वापस ले लिया है।

15226 टन मैदा/सूजी का निर्यात: सरकार ने गाम्बिया को 50,000 टन टूटे हुए चावल का निर्यात करने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि भारत एक बार में गाम्बिया को सारा चावल निर्यात नहीं करेगा। वह 6 महीने में नियम के तहत पूरा चावल भेज देंगे। इसके अलावा 48,804 टन भारतीय चावल एनसीईएल के जरिए भूटान को बेचा जाएगा। वहीं, सरकार भूटान को 14,184 टन गेहूं की आपूर्ति करेगी, वह 5,326 टन आटा और 15,226 टन मैदा/सूजी का निर्यात भी करेगी।

चावल निर्यात की अनुमति दी गई: दिलचस्प बात यह है कि कुछ निर्यातकों ने निर्यात कोटा आवंटन की प्रक्रियाओं को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में मामले दायर किए थे, जो पड़ोसी देशों से शिपमेंट के पिछले अनुभव पर आधारित थे। सरकार द्वारा स्वीकृत 898804 टन टूटे हुए चावल में से 5 लाख टन का आवंटन इस शर्त के साथ किया गया है कि इसका निर्यात अगले छह महीनों में होगा। इसके अलावा भारत ने इंडोनेशिया और माली को 2 लाख टन का आवंटन किया है सरकार ने 1 लाख टन टूटे चावल के निर्यात की अनुमति दी है।

जारी हुए नए आदेश: टूटे हुए चावल निर्यात पर सरकार द्वारा गुरुवार, को जारी एक अधिसूचना में विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कहा कि इस अधिसूचना (30 नवंबर) के परिणामस्वरूप व्यापार सूचना संख्या 08/2023 दिनांक 20 जून, 2023 और व्यापार सूचना संख्या 17/2023 और 18/2023 दिनांक 28 जुलाई , 2023 रद्द कर दिया गया है।

कृषि ड्रोन की खेती

कृषि भूमि ब्यूरो

देश में कृषि ड्रोन का इस्तेमाल होने लगा है, तब से इसने किसानों का काम आसान कर दिया है। अब कीटनाशकों और तरल उर्वरकों जैसे नैनो डीएपी, नैनो यूरिया आदि का छिड़काव आसान हो गया है। अब घंटों का काम मिनटों में हो रहा है। कृषि ड्रोन के इस्तेमाल से किसानों की लागत में कमी आने के साथ ही फसलों का नुकसान भी कम होने लगा है और इसी कारण इन दिनों कृषि ड्रोन की मांग लगातार बढ़ रही है। कृषि ड्रोन का संचालन करने वाली कंपनियों को बड़ी संख्या में प्रशिक्षित वैध ड्रोन पायलटों की आवश्यकता महसूस हो रही है।

गौरतलब है कि इस समय देश में बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके 2026 तक बढ़कर 6 लाख से अधिक होने की संभावना है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह बाजार कितनी तेजी से बढ़ रहा है। किसानों के अलावा, निमार्ता और किराए के ड्रोन भी कृषि ड्रोन की बढ़ती मांग से उत्साहित हैं। किसानों में ड्रोन पायलट बनने की दिलचस्पी इसलिए बढ़ी है क्योंकि सरकार ड्रोन खरीदने के अलावा इसकी ट्रेनिंग में भी अनुदान दे रही है। प्रशिक्षित पायलटों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि हर ड्रोन के लिए एक प्रशिक्षित पायलट होना अनिवार्य है। मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों में चयनित व्यक्तियों को ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किसान ड्रोन प्रशिक्षण का कार्यक्रम भोपाल रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन (आरपीटीओ) में आयोजित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि 10 लीटर टैंक क्षमता के कृषि ड्रोन की कीमत फिलहाल 6 से 10 लाख रुपये है। लेकिन महंगा होने के कारण ज्यादातर किसान कृषि ड्रोन किराए पर ले रहे हैं, जिनकी कीमत 500 से 900 रुपये प्रति एकड़ है। ड्रोन से समय बचाने के अलावा, इसके उपयोग से कीटनाशकों और तरल उर्वरकों का छिड़काव करके फसलों की दक्षता भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि ड्रोन के प्रति किसानों की रुचि बढ़ रही है। इसलिए, मध्य प्रदेश में कुल 6 किसान ड्रोन निमार्ता हैं वॉव गो ग्रीन एलएलपी, दक्ष अनमैन्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, गरुड़ एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, मारुत ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड , नेपच्यून एरोटेक प्राइवेट लिमिटेड। , और आईओ टेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड को पंजीकृत किया गया है।

जानिए क्या है कृषि ड्रोन पर अनुदान की

पात्रताः कृषि ड्रोन की खरीद के लिये योजना के तहत अलगझअलग वर्गों एवं संस्थाओं को अलग झअलग अनुदान दिया जाएगा। किसान ड्रोन को क्रय करने पर निम्नानुसार अनुदान प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित की गई है झ व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित , जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों हेतु यंत्र की कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 5,00,000 /- रुपए। व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत अन्य वर्ग के कृषकों एवं कस्टम हायरिंग केन्द्र के संचालकों हेतु यंत्र की कीमत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि 4,00,000 /- रुपए और कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) हेतु यंत्र की कीमत का 75 प्रतिशत अधिकतम राशि 7,50,000 /- रुपए निर्धारित किया गया है।

ड्रोन प्रशिक्षण प्रक्रियाः भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में ड्रोन संचालन हेतु ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस लेना अनिवार्य है, जिन व्यक्तियों के पास अभी लायसेंस नहीं है, वह प्रशिक्षण के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अनुदान योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के कृषक / कस्टम हायरिंग केन्द्र संचालक / कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) श्रेणियों के अंतर्गत इच्छुक कृषक / केन्द्र संचालक / संस्था आवेदन के पात्र हैं। जिन आवेदकों अथवा उनके प्रतिनिधियों के पास ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस नहीं है तथा यदि वे प्रशिक्षण प्राप्त कर इसे लेना चाहते हैं, तो उन्हें विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र में ड्रोन पायलट लायसेंस प्राप्त करने का अवसर मिलेगा । इच्छुक व्यक्ति जो ड्रोन पायलट के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्रशिक्षण शुल्क 30,000 रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) का शुल्क देना होगा। उपरोक्त शुल्क में से 50 प्रतिशत अधिकतम 15,000 रुपए एवं जीएसटी अभ्यर्थी को वहन करना होगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि शासन द्वारा वहन की जाएगी। उपरोक्त आवासीय प्रशिक्षण 07 दिवसीय (5 दिवसीय डीजीसीए द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण एवं 2 दिवसीय किसान ड्रोन संचालन) हेतु आवास एवं भोजन की व्यवस्था निशुल्क रहेगी। जो आवेदक / प्रतिनिधि उपरोक्त प्रशिक्षण में भाग लेना चाहते हैं वे अपना ऑनलाइन आवेदन ६६६.स्त्रीं.ङ्ग्रॅ पर जाकर कौशल विकास का चयन कर अपनी जानकारी एवं अभिलेख अपलोड कर सकते हैं। प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने पर चयनित आवेदकों अथवा उनके प्रतिनिधियों को अनुदान पर किसान ड्रोन खरीदने की पात्रता होगी।

अर्जुन मुंडा बने देश के नए कृषि मंत्री, एमपी की राजनीति में एक्टिव होंगे तोमर

कृषि भूमि ब्यूरो

अर्जुन मुंडा देश के नए केंद्रीय मंत्री होंगे। अर्जुन मुंडा झारखंड के रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतारा गया था जिसमें उन्होंने दिमानी से जीत हासिल की थी। इसके बाद तोमर को मध्य प्रदेश की राजनीति में लाने का फैसला किया गया। एक दिन पहले ही उन्होंने संसद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद गुरुवार रात नए कृषि मंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा का नाम तय किया गया। अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, इसे देखते हुए मुंडा का नाम प्रमुखता से देखा जा रहा है। तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा खूंटी लोकसभा से सांसद चुने गए थे और वर्तमान में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जनजातीय मामलों के मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन अब उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया है। नरेंद्र तोमर के सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा भी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का प्रभार संभालेंगे।

मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार: अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और रेणुका सिंह सरूता का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। इसके बाद कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया जाएगा। वहीं अर्जुन मुंडा को नरेंद्र सिंह तोमर और गजेंद्र सिंह शेखावत के राजीव चंद्रशेखर को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया जाएगा। राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को उनके मौजूदा विभागों के अलावा, जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया जाएगा। राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा, जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। अर्जुन मुंडा तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और मई 2019 में उन्हें जनजातीय मामलों का केंद्रीय मंत्री नियुक्त किया गया।

मुंडा सीएम रह चुके हैं: अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी गिनती भाजपा के वफादार नेताओं में होती है। उनकी भूमिका को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें झारखंड से केंद्र में बुलाया और अलग-अलग मंत्रालयों में जगह दी. अब उन्हें केंद्र में कृषि मंत्री की अहम भूमिका दी गई है। झारखंड की राजनीति को इसलिए भी ध्यान में रखा गया है क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। इसे देखते हुए भारत सरकार ने उनकी जिम्मेदारी बढ़ा दी है।

टोल फ्री नंबर: अब फसल बीमा की शिकायतों को दूर करना और भी आसान

कृषि भूमि ब्यूरो

भारत सरकार किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) योजना चला रही है। यह भारत की प्रमुख फसल-बीमा योजना है , जिसे दुनिया की सबसे बड़ी योजना में गिना जाता है। इस योजना के तहत, किसानों को वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए रबी और खरीफ दोनों फसलों का बीमा किया जाता है। यह योजना विशेष रूप से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार और फसल के नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए है। कम करने के लिए डिजाइन किया गया।

क्योंकि पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को सिर्फ 2 फीसदी प्रीमियम पर फसलों का बीमा किया जाता है. शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। इस प्रकार, किसानों को बहुत सस्ती दरों पर इस योजना से बीमा का लाभ मिलता है। पीएम फसल बीमा योजना से अब तक किसानों को लाखों रुपये का मुआवजा मिल चुका है। ऐसे में इस योजना को लेकर किसानों की शिकायतें भी आ रही हैं. इसे करना अब बहुत आसान हो गया है। अब किसान इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

कैसे करें शिकायत?: आपको बता दें कि फसल बर्बाद होने के बाद किसानों को बीमा लेने और बीमा की शिकायत करने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसान इस टोल फ्री नंबर 14447 पर आसानी से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इस नंबर 14447 पर कॉल करना होगा। फिर आपको अपने दस्तावेजों और समस्याओं के बारे में जानकारी दें। इसके बाद आपको एक टिकट आईडी दी जाएगी। फिर शिकायत दर्ज करने के बाद, आपको एक एसएमएस प्राप्त होगा। इसके बाद आपको अपनी शिकायत का पालन करना होगा।

फसल बीमा का उद्देश्य क्या है?: प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2016 में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, सरकार किसानों को बेमौसम बारिश, सूखे और अन्य प्राकृतिक या स्थानीय आपदाओं के कारण फसल के नुकसान से राहत प्रदान करती है।

पंजीकरण कैसे करें?: पीएमएफबीवाई योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले pmfby.gov.in आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और खुद को रजिस्टर करें। इस योजना के तहत किसान किसी भी बैंक से बीमा करवा सकते हैं।

बागवानी फसल उत्पादन इस बार 3500 लाख टन को कर सकता है पार, सरकार ने दी जानकारी

कृषि भूमि ब्यूरो

किसानों की मेहनत, वैज्ञानिकों की खोज और सरकारों की नीतियों के कारण पिछले कुछ वर्षों में देश में बागवानी फसलों का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। बागवानी फसलों को बढ़ाने के लिए सरकार 2014-15 से राज्यों में समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) लागू कर रही है। उद्यानिकी फसलों में किसानों को अधिक लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार ने अनुमान लगाया है कि 2022-23 के दौरान देश में कुल बागवानी उत्पादन 351.92 मिलियन टन हो सकता है। वर्ष के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन 329.69 मिलियन टन से अधिक है। वर्तमान में, भारत दुनिया में सब्जियों और फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। केला, नींबू, , पपीता, भिंडी जैसी कई फसलों के उत्पादन में देश पहले स्थान पर है। किसानों की मेहनत, वैज्ञानिकों की खोज और सरकारों की नीतियों के कारण पिछले कुछ वर्षों में देश में बागवानी फसलों का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार समग्र विकास, क्षेत्र वृद्धि, उत्पादन और फसल पोरान्त अवसंरचना के सृजन के लिए वर्ष 2014-15 से राज्यों में समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है। एमआईडीएच के तहत गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री, फल, सब्जियां, मसाले और वृक्षारोपण फसलों के उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। संरक्षित खेती और कटाई के बाद प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के निर्माण, किसानों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आदि के लिए सहायता दी जा रही है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन लागू करेगी सरकार: भारत सरकार चावल, गेहूं, मोटे अनाजों, पोषक अनाजों (श्री अन्न) और दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) का कार्यान्वयन कर रही है. एनएफएसएम के तहत, प्रथाओं के बेहतर पैकेज पर क्लस्टर प्रदर्शन, फसल प्रणालियों पर प्रदर्शन, बीज उत्पादन और उच्च उपज वाली किस्मों का वितरण किया जाएगा। उन्नत कृषि मशीनरी, कुशल जल अनुप्रयोग उपकरण, पौध संरक्षण उपाय, पोषक तत्व प्रबंधन, मृदा सुधार, प्रसंस्करण और कटाई के बाद के उपकरण और फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण आदि, जैसे कार्यों के लिए राज्यों के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान की जा रही है।

जानिए कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा क्या बोले: मिशन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और राज्य कृषि का भी समर्थन किया है। इसमें विषय विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों की देखरेख में विश्वविद्यालयों (एसएयू), कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) द्वारा किसानों को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और हस्तांतरण का प्रावधान है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

क्या देश में शुरू होने वाला है खाद्यान संकट?

आयात किया जा सकता है गेहूं

कृषि भूमि ब्यूरो

रबी का मौसम अपने चरम पर है। इस बार रबी सीजन में चुनावी रंग भी बढ़ गया है। उदाहरण के लिए, कई राज्यों में किसान अपनी खेती के साथ-साथ राजनीति की गर्मी का भी आनंद ले रहे हैं। इस रबी सीजन में छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने अगले 5 साल तक देश की 80 करोड़ आबादी को मुफ्त गेहूं और चावल की गारंटी दी है। जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी की इस गारंटी के अलावा कई राज्यों के किसानों ने रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं की बुआई पूरी कर ली है। वहीं कई राज्यों के किसान गेहूं की बुवाई में पिछड़ रहे हैं। इन किसानों को देखते हुए करनाल स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड जौ रिसर्च यानी आईआईडब्ल्यूबीआर को 25 दिसंबर तक गेहूं की बुआई पूरी करनी है। यह पूरी कवायद इसलिए है ताकि देश-दुनिया की एक बड़ी आबादी की थाली में प्रोटीन का मुख्य आधार रोटी की मात्रा हो। वास्तव में, भारत गेहूं उत्पादन के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में से एक है। भारत में रबी सीजन में गेहूं उगाया जाता है, जो देश की 140 करोड़ आबादी के साथ-साथ दुनिया के कई देशों के नागरिकों का पेट भरने के लिए मुख्य आहार है।

गेहूं बफर स्टॉक और गेहूं की खुले बाजार में बिक्री: गेहूं के स्टॉक और कीमतों को कम करने के उद्देश्य से गेहूं की खुले बाजार में बिक्री देश में गेहूं संकट की ओर इशारा कर रही है। दरअसल गेहूं के मामले में भारत दुनिया के सामने एक ताकत है, लेकिन पिछले दो सालों से गेहूं भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। मार्च 2022 में समय से पहले गर्मी के कारण गेहूं का उत्पादन प्रभावित हुआ था, तब से गेहूं का निर्यात बंद हो गया है। वहीं, पिछले साल अप्रैल में बामोसम बार से गेहूं का उत्पादन प्रभावित हुआ था। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, लेकिन गेहूं का बफर स्टॉक 6 साल से नीचे चल रहा है। नवंबर में गेहूं का बफर

स्टॉक 210 लाख मीट्रिक टन है। यह वह अवधि है। जिसमें गेहूं की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। साथ ही यह चुनावी साल है। ऐसे में सरकार लगातार कीमत को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत ओपन मार्केट सेल के तहत गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके लिए बफर स्टॉक का इस्तेमाल किया जाना है। ऐसे में गेहूं का बफर स्टॉक और कम हो सकता है, जो चिंता का विषय बना हुआ है।

बुआई कम, अल नीनो संकटः गेहूं की बुआई जारी है, लेकिन सूखे ने गेहूं की बुआई पर भारी असर डाला है। वास्तव में, अक्टूबर में सामान्य से कम एसएचआई दर्ज किया गया था। वहीं, नवंबर में बार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। तापमान गर्म होने से जहां गेहूं की बुआई प्रभावित हुई है। पिछले साल की तुलना में दिसंबर के पहले सप्ताह में रकबे में 4 फीसदी की कमी आई है। माना जा रहा है कि इस साल गेहूं की बुआई का रकबा पिछले साल के मुकाबले 4 से 5 फीसदी कम रह सकता है। वहीं, इस साल को अल नीनो का साल घोषित किया गया है। माना जा रहा है कि फरवरी के बाद अल नीनो का असर तेज हो जाएगा।

गर्मी के कारण उत्पादन में आयी थी गिरावटः 2022 में मार्च में अत्यधिक गर्मी के कारण गेहूं का उत्पादन प्रभावित हुआ था। अप्रैल 2023 में बेमौसम बारिश ने गेहूं पर कहर बरपाया था। अब जबकि 2024 को अल नीनो का साल कहा जा रहा है तो गेहूं का उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है।

आयात की बात और रूस से क्या उम्मीद की जाएः सरकार ने गेहूं आयात पर 40 फीसदी ड्यूटी लगा दी है, लेकिन जिस तरह से गेहूं के मोर्चे पर खबरें सामने आ रही हैं, वह गेहूं आयात की ओर इशारा कर रही है। बुआई का रकबा कम होने के साथ ही अल नीनो की वजह से उत्पादन शुरू होने का भी अनुमान है। देश को गेहूं संकट से बचाने के लिए गेहूं आयात योजना यह आपके सामने है। ऐसे में रूस से गेहूं का आयात करना भारत के लिए फायदेमंद होगा। भारत के बाद रूस शीर्ष गेहूं उत्पादक देशों में से एक है। इसलिए यह दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। रूस-यूक्रेन की वजह से यूरोप यिन यिन रूस से गेहूं का आयात नहीं कर रहा है। इसलिए पिछले सीजन में रूस में गेहूं की बंपर पैदावार हुई है। तो वहीं भारत के साथ रूस के संबंध भी बेहतर हैं। बेशक अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की जबरदस्त मांग है, लेकिन संभावना है कि भारत अपने कूटनीतिक कौशल के दम पर रूस से कम कीमत पर गेहूं का आयात कर सकता है, जो भारत में संभावित गेहूं संकट की मार न पड़ने का समाधान हो सकता है।

रंग लायी सरकार की मुहिम, सितंबर में कृषि उत्पादों का निर्यात हुआ कम

कृषि भूमि ब्यूरो

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के अगस्त में कृषि जिंसों का निर्यात 27.94 लाख टन रहा था । मूल्य के हिसाब से कृषि जिंसों का निर्यात सितंबर में घटकर 14,153 करोड़ रुपये रह गया, जो चालू वित्त वर्ष के अगस्त में 18,128 करोड़ रुपये था। कृषि उत्पादों के निर्यात पर केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले का असर दिखने लगा है। कृषि निर्यात संवर्धन निकाय एपीडा के अनुसार बासमती चावल सहित अन्य खाद्य वस्तुओं का निर्यात इस साल सितंबर में घटकर 17.93 लाख टन रह गया। जबकि अगस्त में यह आंकड़ा 2.794 करोड़ टन था। खास बात यह है कि अप्रैल और मई में कृषि उत्पादों का निर्यात करीब 33 लाख टन रहा। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के अगस्त में कृषि जिंसों का निर्यात 27.94 लाख टन रहा था। मूल्य के संदर्भ में कृषि उत्पादों का निर्यात सितंबर में घटकर 14,153 करोड़ रुपये रह गया, जो चालू वित्त वर्ष के अगस्त में 18,128 करोड़ रुपये था। खास बात यह है कि सितंबर महीने के दौरान गैर-बासमती 425,000 टन, बासमती चावल 1,21,000 टन, प्याज 1,51,000 टन और भैंस का मांस 121427 टन, निर्यात किया गया।

47 कृषि जिंसों के निर्यात के आंकड़े रखता हैः वहीं, अप्रैल से सितंबर के बीच कृषि जिंसों का कुल निर्यात 1.7227 करोड़ टन रहा। कहा जा रहा है कि देश में महंगाई को काबू में करने के लिए निर्यात पर कुछ शर्तें और नियम लागू किए जाने की वजह से निर्यात में गिरावट आई है। विशेष रूप से बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) में गिरावट आई है।

50 से 60 रुपये किलो बिक रहा है प्याजः आपको बता दें कि हाल ही में खबर आई थी कि केंद्र सरकार ने देश में बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए प्याज के निर्यात पर एक बीमारी लगा दी है। अब देश के व्यापारी अगले साल 31 मार्च तक प्याज का निर्यात नहीं कर पाएंगे। सरकार को उम्मीद है कि उसके इस फैसले से देश में प्याज का स्टॉक बढ़ेगा, जिसकी वजह से कीमतों में गिरावट आएगी। प्याज अब काफी महंगा हो गया है। यह 50 से 60 रुपये किलो बिक रहा है।

यूपी धान खरीद

धान खरीद में आएगी तेजी

48 घंटे के अंदर किसानों को होगा भुगतान, सरकारी ने जारी किए निर्देश

कृषि भूमि ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में सरकारी धान की खरीद में तेजी लाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में गुरुवार को लखनऊ मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में धान खरीद को लेकर एक महत्वपूर्ण मंडलीय समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने धान खरीदी से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों के धान की खरीद

का भुगतान अविलंब समय पर किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित संस्थाएं धान खरीदी के 48 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान सुनिश्चित करें। असल में राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार धान खरीद में होने वाली गड़बड़ी को लेकर सख्त है और इसके लिए शासन स्तर पर सभी मंडल आयुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों से प्राथमिकता के आधार पर धान खरीदा जाए। सभी धान क्रय केन्द्रों का संचालन गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी प्रत्येक सप्ताह धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण करें और प्रतिदिन क्रय केंद्रों का फीडबैक लें। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा बताया गया कि लखनऊ मंडल में 9,95,000, मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य , निर्धारित किया गया है। लखनऊ में 29 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, इस दौरान एक नवंबर से धान क्रय केंद्रों पर खरीद शुरू कर दी गई है। इस क्रम में संभाग के सभी जिलों के धान क्रय केंद्र का मंडलायुक्त द्वारा फीडबैक लिया गया। संबंधित अधिकारी द्वारा बताया गया हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और रायबरेली जिलों में बनाए गए कुल 573 क्रय केंद्रों पर 617 वाहनों में जीपीएस लगाया गया है। डॉ. रोशन जैकब ने शेष वाहनों में तत्काल जीपीएस लगवाने के निर्देश दिए।

लखनऊ के मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने निर्देश जारी किए: मंडलायुक्त ने कहा कि प्रत्येक क्रय केन्द्र पर उपकरणों (इलेक्ट्रॉनिक कांटा, नमी मापक यंत्र एवं विनिंग फैन एवं ई-पॉप मशीन) की शत-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए और कहा कि पारदर्शी तरीके से गुणवत्तापूर्ण धान खरीदी एवं शासन की मंशा के अनुरूप किसानों को त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी धान क्रय केन्द्रों पर होल्डिंग और बैनर भी सुनिश्चित किए जाएं। साथ ही केन्द्रवार धान उपार्जन की समीक्षा संबंधित अधिकारी स्वयं करें। उन धान खरीदी केन्द्रों पर विशेष फोकस किया जाए, जिनकी खरीदी गत वर्ष लक्ष्य की तुलना में अच्छी नहीं हुई थी।

यूपी में 29 फरवरी तक जारी रहेगी धान खरीद: आपको बता दें कि धान खरीदी की सरकारी प्रक्रिया अगले साल 29 फरवरी तक चलेगी और जो किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचना चाहते हैं वह इन केन्द्रों में बेच सकते हैं।

चीनी उत्पाद

कृषि भूमि ब्यूरो

एक बार फिर आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ सकती है। क्योंकि देश में चीनी उत्पादन में गिरावट आई है। सहकारी एनएफसीएसएफएल ने शुक्रवार को कहा कि चालू सीजन 2023-24 के पहले दो महीनों में चीनी उत्पादन में 10.65 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। एनएफसीएसएफएल के अनुसार, अक्टूबर-नवंबर के दौरान देश में चीनी का उत्पादन केवल 43.2 लाख टन रहा। जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह आंकड़ा 48.3 लाख टन था। हालांकि, चीनी का मौसम अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में से एक है। अगर यहां चीनी के

पड़ेगी महंगाई की मार

न में 10% की गिरावट की आशंका

उत्पादन में गिरावट आती है तो पूरी दुनिया में चीनी की कीमतों पर असर पड़ सकता है। हालांकि पिछले दिनों के भीतर की चीनी की कीमत में लगातार बढ़ोत्तरी देखी जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में देश में महंगाई भी बढ़ सकती है। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड (एनएफसीएसएफएल) के अनुसार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में कम उत्पादन के कारण देश के कुल चीनी उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है।

उत्पादन 11 लाख टन रहा: देश के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन इस सीजन के अक्टूबर-नवंबर में केवल 13.5 लाख टन रहा, जो एक साल पहले की समान अवधि में 20.2 लाख टन था। देश के तीसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य कर्नाटक में भी चीनी का उत्पादन पिछले साल के 12.1 लाख टन की तुलना में घटकर 11 लाख टन रह गया।

दो महीने में चीनी की रिकवरी 8.45% थी: सहकारी संस्था ने एक बयान में कहा कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन में वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में उत्पादन पिछले साल की समान अवधि के 10.6 लाख टन की तुलना में बढ़कर 13 लाख टन हो गया। खास बात यह है कि यूपी में चालू सीजन के पहले दो महीनों में चीनी रिकवरी 8.45 फीसदी रही थी।

33 मिलियन टन से कम: यहां तक कि चालू चीनी मिलों की संख्या 451 की तुलना में 433 है, जो कम है। हालांकि, एनएफसीएसएफएल ने 2023-34 सत्र के लिए कुल चीनी उत्पादन 2.915 करोड़ टन रहने का अनुमान लगाया है, पिछले सत्र के 3.3 , करोड़ टन से कम है।

गन्ने की कीमतों से दबाव में यूपी सरकार, लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी कर सकते हैं ऐलान

लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में गन्ने को लेकर सियासी जंग छिड़ सकती है। पंजाब और हरियाणा

सरकार द्वारा गन्ने के दाम बढ़ाए जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश के लिए मुसीबत बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी के शासन वाले पंजाब में गन्ने का रेट देश में सबसे ज्यादा रहा है। अब यहां किसानों से 391 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ना खरीदा जाएगा। जबकि गन्ना मूल्य देने के मामले में भाजपा देश में दूसरे नंबर पर आ गई है। नवंबर से शुरू होने वाले नए गन्ना पेराई सत्र के लिए सरकार प्रदेश के अपने किसानों को 386 रुपये प्रति क्विंटल देगी, जबकि अगले सीजन के लिए यह 400 रुपये प्रति क्विंटल होगी। यह एक तरह का चुनावी दांव है। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश में किसानों को वर्तमान में केवल 350 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की ओर से कीमतें बढ़ाने का दबाव है। किसान शक्ति संघ के नेता पुष्पेंद्र सिंह का कहना है कि यूपी सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है लेकिन पंजाब और हरियाणा के मुकाबले यहां किसानों को काफी कम पैसा मिल रहा है। यूपी में कीमत पंजाब से 41 रुपये और हरियाणा से 36 रुपये कम है। लोकसभा चुनाव में किसान इसे मुद्दा बनाएंगे। यूपी में अब गन्ने का रेट कम से कम 400 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए।

यूपी में सबसे ज्यादा कीमत बीएसपी सरकार में हुई: उत्तर प्रदेश में गन्ने का सबसे अच्छा दाम बसपा सरकार में मिला था। 2007 में जब मायावती ने सरकार संभाली थी तब गन्ने की कीमत 125 रुपये प्रति क्विंटल थी। जिसे उन्होंने पांच साल में 115 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 240 रुपये कर दिया। इसके बाद अखिलेश सरकार ने अपने पांच साल में दाम 65 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिए। जहां तक योगी आदित्यनाथ का सवाल है, उन्होंने अपने पद पर बने रहने का फैसला किया है। साढ़े चार साल के कार्यकाल में इसे केवल 35 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 350 रुपये प्रति क्विंटल किया गया. तब से किसान दाम बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। हर देश और पंजाब में कीमतें बढ़ती रहीं, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं हुआ।

हर साल एक साथ दो सीजन की कीमत बढ़ाई जाती थी: एक तरफ यूपी के किसान लंबे समय से गन्ने का रेट बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हर सरकार ने एक साथ दो सीजन का रेट बढ़ा दिया है।

सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अगले साल जिन दिनों गन्ने का रेट घोषित होगा, उन दिनों आचार संहिता लगाई जाएगी। इसलिए विभाग के परामर्श से अगले वर्ष के लिए गन्ने का रेट 400 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। किया जाता है। इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गन्ना किसानों को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए उचित मूल्य मिले। गन्ने की दरों में उल्लेखनीय वृद्धि कर किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

यूपी में होता है गन्ने का 47 फीसदी उत्पादन: उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार, देश के कुल गन्ना उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 47.4 प्रतिशत है। जबकि 25.3 प्रतिशत के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। दूसरी ओर, हरियाणा और पंजाब में देश के कुल गन्ना उत्पादन का केवल 2 प्रतिशत हिस्सा है। पंजाब में 16 और हरियाणा में 14 चीनी मिलें हैं। दूसरी ओर, यूपी में 200 और महाराष्ट्र में 120 चीनी मिलें चल रही हैं। ऐसे में छोटे राज्यों ने यूपी जैसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं।

किसानों को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला

अब 391 रुपये मिलेगा गन्ने का रेट

गन्ना किसानों को लेकर पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए गन्ने का रेट बढ़ाकर 391 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इस तरह पंजाब गन्ना किसानों को सबसे ज्यादा दाम देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार की घोषणा के साथ ही अब पंजाब के किसानों को 391 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा। यह दर देश में सबसे अधिक है। इसके बाद हरियाणा और अन्य राज्यों का स्थान है। गन्ने का दाम देने में पंजाब पहले नंबर पर और हरियाणा दूसरे स्थान पर है। हरियाणा में किसानों को 386 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ना मिलता है। यूपी और उत्तराखंड के किसानों को 350 रुपये का दाम मिलता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने की कीमत इससे भी कम है।

गन्ने का मूल्य बढ़कर 391 रुपये प्रति क्विंटल हुआः हाल ही में पंजाब सरकार ने कहा था कि राज्य के गन्ना नियंत्रण बोर्ड और चीनी मिल मालिकों के साथ बैठक की जाएगी और गन्ने के मूल्य पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद सरकार ने गन्ने का दाम बढ़ाने का फैसला किया। पंजाब के किसान गन्ने की कीमत बढ़ाने के लिए कई सालों से आंदोलन कर रहे थे। किसानों ने कहा कि जब हरियाणा 386 रुपये दे रहा है तो पंजाब सरकार इसे बढ़ाक्यों नहीं रही है। किसानों ने कीमतें बढ़ाने के लिए सड़क की पटरियों और रेलवे पटरियों को भी अवरुद्ध कर दिया था। आखिरकार किसानों की मांगें मान ली गई हैं। इसके साथ ही पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां गन्ना किसानों को 391 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे।

गन्ना मिल मालिकों से बातचीतः हाल ही में किसान प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने बयान में कहा था कि सरकार आने वाले दिनों में गन्ने के दाम बढ़ाकर किसानों को खुशखबरी देगी। मान ने कहा था कि सरकार जल्द ही गन्ना मिल मालिकों के साथ बातचीत करेगी और कीमतें बढ़ाने पर फैसला लेगी।

इन राज्यों में गन्ने की कीमतेंः दरअसल, पंजाब के किसान गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। इस बढ़ोतरी से पहले पंजाब में गन्ने का प्रति क्विंटल भाव 380 रुपये था। पड़ोसी राज्य हरियाणा में गन्ना 386 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। लेकिन पंजाब के किसान 450 रुपये प्रति क्विंटल की मांग कर रहे हैं।

जालंधर में सड़कों में बैठे थे किसानः कुछ दिन पहले पंजाब में गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर कई दिनों से धरने पर बैठे गन्ना किसानों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के आश्वासन पर अपना धरना वापस ले लिया था। जालंधर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठे किसानों ने रेल ट्रैक को अवरुद्ध करने का भी फैसला किया था, लेकिन मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद पटरियों को खाली कर दिया गया।

देश: अक्टूबर में बढ़ा चाय का उत्पादन

दक्षिण राज्यों की उत्पादन क्षमता में आयी गिरावट

कृषि भूमि ब्यूरो

देश के सबसे बड़े चाय उत्पादक राज्य असम ने भी अक्टूबर में 10.43 करोड़ किलोग्राम से अधिक चाय का उत्पादन किया। देश में चाय का उत्पादन इस साल अक्टूबर में 12.06 प्रतिशत बढ़कर 1.828 करोड़ किलोग्राम रहा। पिछले साल इसी महीने में यह 16.31 करोड़ किलोग्राम था। चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में चाय का उत्पादन अक्टूबर में बढ़कर 5.49 करोड़ किलोग्राम हो गया। जबकि 2022 के इसी महीने में यह 4.97 करोड़ किलोग्राम था। देश के सबसे बड़े चाय उत्पादक राज्य असम ने भी अक्टूबर में 10.43 करोड़ किलोग्राम से अधिक चाय का उत्पादन किया। पिछले साल इसी महीने में राज्य में 9.07 करोड़ किलोग्राम चाय का उत्पादन हुआ था। इसकी तुलना में दक्षिण भारत में उत्पादन मामूली घटकर 1.88 करोड़ किलोग्राम रह गया। एक साल पहले 2022 के अक्टूबर महीने में यह 1.89 करोड़ किलोग्राम था।

ग्रीन चाय का उत्पादन 21.4 लाख तक पहुंचा: आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2023 में सीटीसी किस्म की चाय का उत्पादन 16.77 करोड़ किलोग्राम था, जबकि उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में उत्पादित ऑर्थोडॉक्स चाय का उत्पादन 1.29 करोड़ किलोग्राम था। इस दौरान ग्रीन टी का उत्पादन 21.4 लाख किलोग्राम रहा।

INDIAN COAST GUARD

Blazing the Blue with Elan

Indian Coast Guard ...

An excellent career choice that is both inspiring and rewarding

visit us at : www.indiancoastguard.nic.in

कृषिभूमि

आधुनिक किसान की ज़रूरत

समाचार पत्रिका | RANDOM VIDEOS

HOME | राज्य | खेती बाड़ी | बागवानी | पशु पालन | व्यापार | एग्रो मशीनरी | मौसम | योजनाएं | इवेंट

ताजा खबर

प्याज और मक्का की खरीद में तेजी, एमएसपी पर हो रही है किसानों से खरीद

सरकार दे सकती है गेहूं और आटा स्टॉक लिमिट नियमों में ढील, छापेमारी से परेशान कारोबारियों

20 Hours Ago

बीजनेस | ताजा

सरकार दे सकती है गेहूं और आटा स्टॉक लिमिट नियमों में ढील, छापेमारी से परेशा...

केंद्र सरकार ने गेहूं और आटे की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए आटा...

पशु पालन

इन जानवरों को पालने के लिए सरकार दे रही 3 लाख, ऐसे करें आवेदन

खेती बाड़ी | मौसम

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कैसा रहेगा विपरजॉय चक्रवात, जानने के लिए पढ़िए...

बीजनेस

छत्तीसगढ़ के सौर सुजला योजना से सिंचाई में हुई बढ़ोतरी

उत्तर प्रदेश | बीजनेस

गन्ने की कीमतों से दबाव में यूपी सरकार, लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी कर...

अन्य समाचार

मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पांच साल के लिए बढ़ाई गयी 81 करोड़ गरीबों के लिए...

ग्रामीण किसानों को बिना खरीदी के मिलेंगे 10 लाख, ऐसे करें आवेदन

असम में बाढ़ से हालात खराब, मुसीबत में 5 लाख लोगों की जान

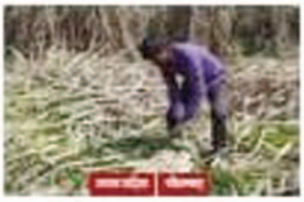

गन्ने की कीमतों से दबाव में यूपी सरकार, लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी कर...

लोकप्रिय समाचार

असम में 5 लाख 50 धान की खरीद, 80,000 किसानों के खातों में पहुंचे...

मिश्रा मौसम का मिजाज, उत्तराखंड और केरल में भारी बारिश से हिमपात...

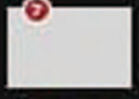

यूपी सरकार ने किसानों के हित पर लिया 80 परिवारों टूट का ऐलान, किस...

खुशखबरी चीनी के सस्ते में हुआ इजाफा, 1000 रुपये तक गिरेंगे दाम

ट्रेंडिंग न्यूज़

गन्ना किसानों को अब एक क्लिक पर ऑनलाइन मिलेगी अधिकतम सेंट की सुविधा

01

1 Min Ago

योगी प्रशासन ने यूपी के किसानों को दिया तोहफा, हुआ सभी में हैरत करोड़ों रुपया

यूपी में सभी प्रकार और गन्ना की खरीद में तेजी, एमएसपी पर हो रही है किसानों से खरीद

ताजा खबर

असम में 5 लाख 50 धान की खरीद, 80,000 किसानों के खातों में पहुंचे...

मिश्रा मौसम का मिजाज, उत्तराखंड और केरल में भारी बारिश से हिमपात...

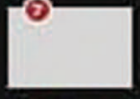

यूपी सरकार ने किसानों के हित पर लिया 80 परिवारों टूट का ऐलान, किस...

खुशखबरी चीनी के सस्ते में हुआ इजाफा, 1000 रुपये तक गिरेंगे दाम

krishibhoomi.in - Copyright © 2022. Developed By Digitar Media.

Privacy Policy | Contact